सुविचार

॥ प्यार और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। ॥

प्रथम न्यूज

PRATHAM NEWS राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

Website: www.prathamnews.in email:- dainikprathamnews@gmail.com

Pratham News @dainikprathamnews

बल्लेबाजों में खौफ पैदा करना है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए गुरनूर बराड़ ने भरी हुंकार; बैटर्स को दी बड़ी चेतावनी...» पृष्ठ 7 पर

जालंधर, वर्ष: 16 अंक : 168 | दिनांक : शुक्रवार, 19 जून 2026 | सम्पादक : विवेक धीर | सम्पर्क: | 97796-00900 | पन्ने- 8 | मूल्य: ₹ 2.00/- | RNI No I PUNHIN/2010/36540

मध्य पूर्व में शांति का नया अध्याय

अमेरिका-ईरान समझौते पर ट्रंप और पेजेशकियन ने किए हस्ताक्षर

समझौते का मुख्य उद्देश्य होमुंज जलडमरूमध्य को तुरंत खोलना

» प्रथम न्यूज । पेरिस (फ्रांस)
18 जून (एजेंसी)

मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है।

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते के मसौदे पर प्रारंभिक सहमति बन गई है। मसौदे में सैन्य गतिविधियों को रोकने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, ईरान के पुनर्निर्माण में सहयोग और परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार शाम फ्रांस के वर्साय पैलेस में आयोजित रात्रिभोज के दौरान अमेरिका-ईरान समझौते के मसौदे पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस और फॉक्स न्यूज ने अपने एक्स हैंडल पर सबसे पहले इसकी पुष्टि की। इसके बाद यह खबर दुनिया में आग

की तरह फैल गई। ईरान के प्रेस टीवी, गल्फ न्यूज, अल जजीरा, सीएनएन, टाइम पत्रिका और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने, प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत और 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते की दिशा में कदम शामिल हैं।

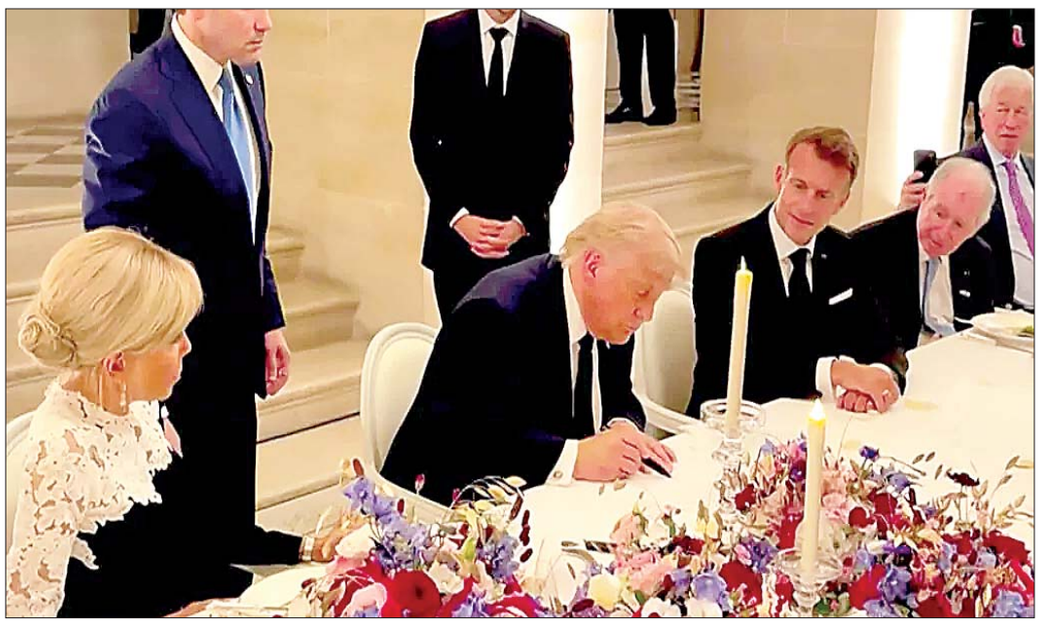

बताया जाता है कि ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अमेरिका ने इस दस्तावेज को %संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामी गणराज्य ईरान के बीच इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन% के रूप में जारी किया है। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य होमुंज जलडमरूमध्य को तुरंत खोलना, ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार से जुड़े मुद्दों का समाधान करना और प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत देने के लिए एक ढांचा तैयार करना है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्त इस्माइल बधाई ने पुष्टि की कि समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देकर दोनों पक्षों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर ओमान और अन्य देशों के साथ काफी समय से परामर्श चल रहा 5 था। साथ ही होमुंज जलडमरूमध्य के प्रबंधन से जुड़े अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी थी। बधाई ने कहा कि अब समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। होर्मुज जलडमरूमध्य पर इस्लामी गणराज्य ईरान की संप्रभुता और अधिकार सुरक्षित राहेंगे।

मसौदे के 14 बिंदु

1- सभी तरह के संघर्ष रुकेंगे अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देशों ने तत्काल प्रभाव से सभी सैन्य अभियानों को समाप्त करने और भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध या सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करने का संकल्प लिया है। इसमें लेबनान से जुड़े संघर्ष भी शामिल हैं। लेबनान की संप्रभुता और यक्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा।

2- एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान: दोनों देश एक-दूसरे की स्वतंत्रता, दक्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाएंगे।

3- 60 दिनों में अंतिम समझौते का लक्ष्य।

4- अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटेगी इसमें शर्त है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकाबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 30 दिन के भीतर इसे पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

5. होर्मुत्र जलडमरूमध्य ईरान 60 दिन तक फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच वाणिज्यिक जहाजों को मुफ्त और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराएगा। तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने तथा समुद्री बारूदी सुरंगों की सफाई के बाद 30 दिन में कतायात सामान्य स्तर पर पहुंचाने की योजना है।

6- ईरान के लिए 300 अरब डॉलर की आर्थिक योजना।

7- प्रतिबंध हटाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

8- ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। दोनों देश संवर्धित परमाणु सामती के निपटारे, यूरेनियम संवर्धन और अन्य परमाणु जरूरतों पर अंतिम समझौते के तहत विस्तृत चर्चा करेंगे।

9- वार्ता के दौरान यवास्थिति बनी रहेगी।

10- तेल निर्वात को तत्काल राहत एमओयू लागू होते ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़ी बैंकिंग, बीमा तथा परिवहन सेवाओं के लिए विशेष छूट जारी करेगा।

11- अमेरिका ईरान की फ्रीज वा प्रतिबंधित संपत्तियों और धनराशि को उपयोग के लिए उपलब्ध कराने पर सहमत

12-निगरानी तंत्र समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यकारी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

13-अंतिम समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू होगी।

14- अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के जरिए वैधता प्रदान की जाएगी।

संक्षिप्त न्यूज

व्हाट्सएप्प स्टेटस बना साइबर जाल, पूर्व PM गुजराल के बेटे से 7.8 करोड़ की ठगी

नरेश गुजराल के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप्प अकाउंट, 4 दिन में करोड़ों रुपये ट्रांसफर

नई दिल्ली (एएम नाथ)- पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश गुजराल के साथ 7.8 करोड़ रुपये की बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह घटना 12 से 16 जून 2026 के बीच हुई और रकम के लिहाज से राजधानी की सबसे बड़ी साइबर धोखाधड़ी के मामलों में से एक मानी जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगों ने नरेश गुजराल की प्रोफाइल फोटो लगाकर एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और उनकी वित्तीय टीम के एक भरोसेमंद कर्मचारी को संदेश भेजे। संदेश में आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से तत्काल धनराशि ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए। कर्मचारी को यह आभास नहीं हुआ कि संदेश असली नहीं हैं और उसने 12 से 16 जून के बीच चार अलग-अलग आरटीजीएस लेनदेन के जरिए करोड़ों रुपये विभिन्न खातों में भेज दिए।

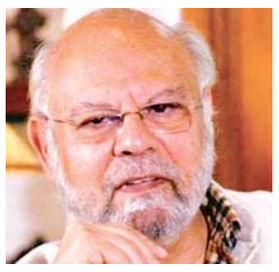

मामले का खुलासा होने पर नरेश गुजराल ने तुरंत दिल्ली की साइबर एजेंसियों को शिकायत दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते लगभग 4 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दी गई है, जिससे उसे निकाला नहीं जा सकता। गुजराल ने बताया कि लेनदेन से पहले बैंक ने उनके मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्हें लगा कि भुगतान के निर्देश स्वयं गुजराल ने दिए हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन को मंजूरी दे दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है।

क्रूड ऑयल में भारी गिरावट!

भारत में सस्ते होंगे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी

नई दिल्ली (ब्यूरो)- अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध रोकने के पीस डील के ऐलान के बाद अंतराष्ट्रीय एनर्जी मार्किट में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें पिछले 111 दिन में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी हैं।

गुरुवार को ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स की कीमत करीब 2% गिरकर 77 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। इसकी वजह से भारत जिस रेट पर कच्चा तेल खरीदता है उसमें भी अच्छी गिरावट दर्ज़ हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की 18 जून, 2026 को जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 17 जून, 2026 को कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की कीमत गिरकर रु.78.48/bbl पर पहुंच गयी। इसकी वजह से जून के पहले 17 दिनों के दौरान कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की औसत कीमत भी घटकर US$ 91.02/bbl हो गयी है।

गुरुवार को ये पूछे जाने पर की अमेरिका-ईरान पीस डील के बाद क्या भारत सरकार कच्चे तेल की कीमतों में आयी गिरावट को देखते हुए पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों से कुछ राहत दे सकती है, जिसपर पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि ये मामले सरकार के संज्ञान में है और अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए खुदरा कीमतों के बारे में फैसला लिया जाएगा।

नई नौकरी पर 15 हजार, PM मोदी आज हजारों युवाओं को देंगे तोहफा

रोजगार योजना में 2400 करोड़ बांटे जाएंगे

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली
18 जून (एएम नाथ)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपये की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत ये प्रोत्साहन राशि आज जारी करेंगे। इस रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य जॉब बढ़ाना, रोजगार को मजबूत बनाना, स्किल बढ़ाना और ऐसे रोजगार में पीएफ, बीमा-पेंशन से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। इस स्कीम से देश में पहले ही 15 लाख रोजगार पैदा किए जा चुके हैं। जबकि लगभग 2 करोड़ रोजगार का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) को ऐसे बनाया गया है कि यह कर्मचारियों और

नौकरी देने वाली कंपनियों दोनों को संगठित जॉब सेक्टर से जोड़ा जा सके। इस स्कीम के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये का इंसेंटिव मिलता है। इससे उन्हें अपने रोजगार को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

कंपनियां नई नौकरियां देने को प्रोत्साहित होती हैं। उन्हें हर कर्मचारी के लिए प्रति माह 3000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलता है। इससे लगातार नौकरियां पैदा होते हैं। उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां चार साल की अवधि के लिए ये प्रोत्साहन राशि ले सकती हैं। अन्य सभी सेक्टर की कंपनियां दो साल के लिए इंसेंटिव का लाभ ले सकते हैं।

करीब 2 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य

PM-VBRY योजना 1 अगस्त 2025 को लागू हुई थी। इसके लिए 99446 करोड़ रुपये के बजट वाली इस स्कीम को लांच किया था। इसका मकसद दो साल की अवधि में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना था। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ नए युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य था। कर्मचारियों और नौकरियों दोनों को मदद देकर यह स्कीम संगठित रोजगार क्षेत्र का विस्तार करना है। साथ ही सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाकर विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका को पूरा करना है।

ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से करारा

ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे बंगाल में नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर के फैसले पर रोक से इनकार

कोलकाता (ब्यूरो) पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक और बड़ा सियासी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल विधानसभा स्पीकर का निर्णय लागू रहेगा। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई आधार नहीं बनता, जिसके चलते अंतरिम राहत दी जाए। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने ममता बनर्जी गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से मना कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है, जिसके बाद याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते मिलेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी।

भिवानी एयरोड्रम को मिली नई उड़ान

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 31 करोड़ रुपये की विमानन परियोजनाओं का किया उद्घाटन

» प्रथम न्यूज । ब्यूरो
18 जून (भिवानी)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नागरिक विमानन के क्षेत्र में हरियाणा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश के विमानन मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल सिविल एयरोड्रम में 31 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए हैंगर और एटीसी भवन के निर्माण से हेलीकॉप्टरों और विमानों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होगा। साथ ही विमान और हेलीकॉप्टरों के रखरखाव एवं तकनीकी कार्यों को भी सुविधा मिलेगी, जिससे भिवानी हवाई पट्टी की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल सिविल एयरोड्रम में अब तक 120 पायलट प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षित पायलटों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने

वाले समय में यहां फ्लाइट ट्रेनिंग गतिविधियों का और विस्तार होगा तथा अधिक संख्या में कुशल पायलट तैयार किए जाएंगे। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा हवाई संपर्क के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हिसार एयरपोर्ट से पहले ही चंडीगढ़, जयपुर और अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। अब जल्द ही जम्मू, अहमदाबाद और दिल्ली के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल और कार्गो टर्मिनल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वर्ष 2027 तक इसे एक विकसित और आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से हिसार को एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे विमानों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी परीक्षण का कार्य प्रदेश में ही संभव हो सकेगा तथा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारत में निर्मित हो रहे 'शत्रुजीत' हेलीकॉप्टर का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर कर्नल रामपाल सुहाग ने जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर के कई पुर्जों का निर्माण और असेंबलिंग अब भारत में ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि वायुसेना, आईटीबीपी तथा अन्य सुरक्षा बलों की ओर से लगभग 1400 हेलीकॉप्टरों की मांग प्राप्त हुई है।

इस अवसर पर सांसद धर्मबीर सिंह, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ तथा बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

फर्जी वीडियो पर CM मान का पलटवार, बोले- मुझे बदनाम करने की साजिश

वीडियो विवाद में ष्टरूमान ने दिखाई 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट, ष्ठत्रक्कको जांच के आदेश

अकाल तख्त की आपत्ति के बीच CM मान का LIVE बयान, कहा- वीडियो में मैं नहीं हूं

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ़
18 जून (एएम नाथ)

पंजाब में कथित विवादित वीडियो को लेकर सियासी और धार्मिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री भगवंत मान के होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने उन्हें गुरु दोषी और पंथ विरोधी करार दिया। हालांकि मुख्यमंत्री मान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वीडियो पूरी तरह फर्जी है और उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत फैलाया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर स्थ्रङ्कश्च आकर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सिख पंथ और पंजाब के सम्मान के लिए कई ऐतिहासिक फैसले

लिए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का सहारा लेकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर लोगों को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है।

मान ने दावा किया कि वीडियो की जांच दो बाहरी फॉरेंसिक लैब से करवाई गई है। उनके अनुसार 1191 फ्रेम के तकनीकी विश्लेषण में एक भी फ्रेम उनके चेहरे, कद-काठी या अन्य शारीरिक विशेषताओं से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं हैं और ऐसा कृत्य करने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में उनके कार्यों और बढ़ती लोकप्रियता से परेशान कुछ लोगों ने यह साजिश रची है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच पंजाब पुलिस के ष्ठत्रक्कको सौंप दी गई है। मान ने निर्देश दिए हैं कि वीडियो बनाने, शूट कराने और फैलाने वालों की पहचान कर उन्हें संगत के सामने लाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

प्रथम न्यूज़
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
पंजाब न्यूज़
Website : www.prathamnews.in

संक्षिप्त न्यूज

मोगा में एक बार फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां, युवक की मौत

दोनों के बीच थी पुरानी रंजिश

मोगा (ब्यूरो)- पंजाब में एक बार फिर गोलियां चलने की खबरें सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब के जिला मोगा में फायरिंग हुई है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के जिला मोगा के सब-डिवीजन बाघापुराना के अंतर्गत आने वाले गांव सुखानंद में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई है। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान गांव चीदा निवासी जसकरण सिंह उर्फ गग्गू के रूप में हुई है। इसके साथ ही गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान अमनदीप सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कोई पुरानी रंजिश थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला की जांच करनी शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें गठित की गई हैं और और लगातार तलाश की जा रही हैं।

मैक्स हॉस्पिटल मोहाली ने मानसा में पल्मोनोलॉजी ओपीडी शुरू की

मानसा (जगमीत घुम्मन)- मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोहाली ने शुक्रवार को लव गैस्ट्रो एंड लिवर हॉस्पिटल , मानसा में पल्मोनोलॉजी ओपीडी शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का मकसद मरीजों के लिए सांस से जुड़ी बीमारियों का बेहतर इलाज उनके करीब पहुंचाना और फेफड़ों व सांस से जुड़ी समस्याओं की समय पर पहचान और इलाज सुनिश्चित करना है। ओपीडी की शुरुआत मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोहाली के पल्मोनोलॉजी कंसल्टेंट डॉ कपिल कुमार की मौजूदगी में की गई।

पल्मोनोलॉजी कंसल्टेंट डॉ कपिल कुमार हर महीने के चौथे शुक्रवार को लव गैस्ट्रो एंड लिवर हॉस्पिटल, मानसा में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शुरुआती सलाह और फॉलो-अप के लिए उपलब्ध रहेंगे।

डॉ कपिल ने कहा कि ओपीडी के शुरू होने से मानसा और आसपास के इलाकों के मरीजों को स्पेशलाइज्ड सलाह, समय पर बीमारी का पता चलने, इलाज के बारे में जानकारी, फॉलो-अप देखभाल और ज़रूरत पड़ने पर एडवांस्ड जांच या खास प्रक्रियाओं के लिए रेफरल की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सांस से जुड़ी बीमारियों को सही ढंग से संभालने और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में बीमारी का जल्दी पता चलना और नियमित निगरानी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।

टीबीएस इंटरनेशनल स्कूल में श्री गुरु अर्जन देव जी का शहादत दिवस मनाया गया

जीरा, 18 जून (अंग्रेज बराड़) - फिरोजपुर-मोगा रोड पर स्थित टीबीएस इंटरनेशनल स्कूल फिरोजशाह, अध्यक्ष डॉ. हीरा लाल शर्मा, उपाध्यक्ष विभोर शर्मा, प्रबंध निदेशक दीपाली शर्मा और महासचिव शिवम शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। स्कूल ने सिखों के पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस को ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से श्रद्धापूर्वक मनाया। विद्यार्थियों ने गुरबानी पाठ और शबद गायन जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने अपने शिक्षकों से सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए 30 मई, 1606 ईस्वी को श्री गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान के बारे में जाना और गुरु के उपदेशों को सुनकर उनसे प्रेरणा ली। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने गुरु जी की करुणा और साहस के आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। प्रधानाध्यापिका मैडम रेखा पासी ने विद्यार्थियों से कहा कि गुरु जी का बलिदान हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करता है।

शंकर कटारिया ने भारत विकास परिषद के 43वें सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया

जीरा, 18 जून (अंग्रेज बराड़) - श्री शांति नाथ बिर्ध आश्रम जीरा में भारत विकास परिषद जीरा द्वारा शुरू किए गए 43वें सिलाई केंद्र का उद्घाटन जिला विकास परिषद के सदस्य श्री शंकर कटारिया ने रिबन काटकर किया! इस अवसर पर धर्मपाल चुघ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे! इस दौरान शंकर कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विकास परिषद जीरा द्वारा किए जा रहे सामाजिक कल्याण कार्य अत्यंत सराहनीय हैं! भारत विकास परिषद की पूरी टीम हर क्षेत्र में सामाजिक कल्याण कार्यों में सहयोग करती रहती है! इस अवसर पर उन्होंने संगठन को पांच सिलाई मशीनें भी भेंट कीं! इस अवसर पर अध्यक्ष महेंद्र पाल और महिला अध्यक्ष नीतू शर्मा ने कहा कि भारत विकास परिषद पांच सूत्रों में सेवा, समर्पण, सहयोग, संस्कार और सामाजिक सेवा का कार्य करती है! यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसकी देश भर में लगभग 2000 शाखाएं हैं! संगठन का उद्देश्य वंचित समाज को सशक्त बनाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर और अपने पैरों पर खड़ा करना है! वर्तमान में, यह संस्था वकिलवाला, माहियांवाला गांव और जीरा बिर्ध आश्रम में तीन सिलाई केंद्र चला रही है, जिनमें 70 लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है! संस्था पिछले 15 वर्षों से सिलाई केंद्र परियोजना चला रही है, जिसके तहत इसने लगभग 2000 लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है! इस अवसर पर संस्था की पूरी टीम ने जनिंदर जैन को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने सिलाई केंद्र के लिए जगह उपलब्ध कराई और पिछले 10 वर्षों से जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों के विवाह में संस्था का सहयोग कर रहे हैं! इस अवसर पर राकेश ग्रोवर सीए, राजेश ग्रोवर और गगन ग्रोवर विशेष रूप से उपस्थित थे और उन्होंने अपनी माता की पुण्यतिथि के अवसर पर संस्था को चार सिलाई मशीनें भेंट कीं।

केवल सिंह ढिल्लों व तरुण चुग श्री हरिमंदिर साहिब, श्री दुर्ग्याणा तीर्थ व श्री राम तीर्थ में हुए नतमस्तक

» प्रथम न्यूज । अमृतसर
18 जून (साहिब दयाल)

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व मध्य प्रदेश से नव-निर्वाचित राज्यसभा सांसद तरुण चुग अपने एक दिसवीय अमृतसर प्रवास के तहत गुरुनगरी पहुंचे जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं के विशाल जनसमूह ने भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू की अध्यक्षता में अमृतसर के भंडारी पुल पर बड़ी गर्मजोशी से ढोल-नगाड़ों तथा जयघोष के नारों के साथ उनका स्वागत किया।

इसके उपरांत दोनों पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के विशाल काफिले के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब नतमस्तक होने पहुंचे, जहाँ उन्होंने गुरु के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत दोनों पदाधिकारीयों ने जलियांवाला बाग़ में पहुँच कर शहीदों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

वहां से दोनो पदाधिकारी श्री दुर्ग्याणा मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री दुर्ग्याणा कमेटी के पदाधिकारियों

द्वारा केवल सिंह ढिल्लों व तरुण चुग को स्मृति चिन्ह व दोशाला देकर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत दोनों पदाधिकारी भाजपा जिला कार्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना स्मारक पहुंचे, जहाँ उनका जोरदार स्वागत भाजपा महिला मोर्चा अमृतसर तथा भाजपा सीनियर सिटिजन सेल द्वारा स्वागत किया गया। दोनों पदाधिकारियों ने कार्यालय में स्थापित शहीद हरबंस लाल खन्ना जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। यहाँ से दोनों पदाधिकारी हॉल बाज़ार के बाहर स्थित श्री गुरु रवि दास मंदिर में नतमस्तक होने पहुंचे, जहाँ संत रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

दोपहर को दोनों पदाधिकारी कंपनी बाग़ स्थित महाराजा रणजीत सिंह को समर्पित बने पैनोरोमा पहुंचे, जहाँ उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को पुष्पांजली अर्पित कर, पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर राज्य की जनता को महाराजा रणजीत सिंह जैसा सुशासन देने का प्रण लिया। इसके उपरांत दोनों पदाधिकारी श्री राम तीर्थ नतमस्तक होने पहुंचे, जहाँ उन्होंने भगवान श्री वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके साथ विशेष रूप से पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक, प्रदेश महासचिव दयाल सिंह सोढ़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष व भाजपा अमृतसर प्रभारी के. डी. भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने प्रवास के दौरान केवल ढिल्लों ने संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉ. भीम राव आंबेडकर जी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भेंट कर देश और समाज के प्रति उनके योगदान को नमन किया।

केवल सिंह ढिल्लों ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अमृतसर के धार्मिक स्थलों में नतमस्तक होकर असीम शांति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के सुशासन, इंसाफ तथा खुशहाली की भावना को पुनर्सृजित और स्थापित करना है।

शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का शासन लोग भलाई, धार्मिक सद्भावना, मजबूत प्रशासन तथा सुरक्षित समाज के रूप में जाना जाता था। उनकी विरासत हमें लोक सेवा, न्याय तथा सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती है।

भाजपा पंजाब के लोगों के साथ मिलकर ऐसे ही पंजाब के निर्माण के लिए वचनबद्ध है, जो उन्नति, शांति व खुशहाली का प्रतीक हो। उन्होंने सभी को मिलकर ऐसे पंजाब के निर्माण में योगदान के लिए आगमी विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाकर पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया।

तरुण चुग ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों व गुरुद्वारे में मारे गए दंपति पर पाकिस्तान सरकार पर बरसते हुए कहा कि वह खुद तथा प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे और पाकिस्तान सरकार पर भी इस मामले में राजनीतिक दबाव बनाकर वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब पंजाब में भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है और इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जनता द्वारा दिए गए बहुमत के फतवे से भाजपा की सरकार बनेगी।

होशियारपुर की लड़कियों ने बरनाला को 95 रन से हराकर सीनियर वूमेन क्रिकेट में रचा इतिहासः डा. रमन घई

» प्रथम न्यूज । होशियारपुर
18 जून (तरसेम दीवाना)

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा करवाई जा रही अंतर जिला सीनियर वूमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमी फाइनल मैच में होशियारपुर की लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला बरनाला टीम को 95 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश करते हुए इतिहास रच दिया।

इस संबंधी जानकारी देते हुए एचडीसीए सचिव डा. रमन घई ने बताया कि बरनाला में खेले गए 50-50 ओवरों के इस सेमी फाइनल मैच में बरनाला की टीम ने टॉस जीतकर होशियारपुर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया तथा होशियारपुर की टीम ने अपनी ओपनर खिलाड़ी पूजा देवी के 77 रन, कप्तान सुहाना के 42 रन, शिवानी के 30 रन व मनप्रीत ओलख के नवाद 11 रनों की बदौलत 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। बरनाला की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए ममता रानी ने 4, अमरजोत कौर ने 2, अक्शिता भगत व सुखमीत कौर ने होशियारपुर के 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। उन्होंनें बताया कि 50 ओवरों में जीत के लिए 196 रनों का लक्ष्य लेकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी बरनाला की टीम होशियारपुर की राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरभि व अंजलि की शानदार गेंदबाजी के आगे पूरी तरह बिखर गई तथा सारी टीम 24.1 ओवरों में केवल 100 रन बनाकर ही आल आउट हो गई। होशियारपुर की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए सुरभि ने 28 रन देकर 6 विकेट, अंजलि सीमर ने 22 रन देकर 2 विकेट तथा ध्रुविका सेठ ने 27 देकर बरनाला के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। डा. घई ने बताया कि इस सेमीफाइनल मैच में बड़ी जीत के साथ होशियारपुर टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंनें बताया कि होशियारपुर का फाइनल मुकाबला 21 जून को पटियाला के साथ पीसीएस स्टेडियम चंडीगढ़ में खेला जाएगा। उन्होंनें होशियारपुर टीम को फाइनल मे पहुंचने पर बधाई देते हुए उन्हें आगे भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।

भारत चुनाव आयोग द्वारा जिला गुरदासपुर के विधानसभा क्षेत्रों के लिए नए ईआरओ और एइआरओ की नियुक्तियों को मंजूरी

» प्रथम न्यूज । गुरदासपुर
18 जून (संदीप सन्नी)

भारत चुनाव आयोग से प्राप्त आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार, जिला गुरदासपुर के विभिन्न विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए नए चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी गई है।

इस संबंधी विस्तृत जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी, गुरदासपुर आदित्य उप्पल ने बताया कि चुनाव कार्यों को और अधिक सुचारू व पारदर्शी बनाने के लिए आयोग द्वारा प्रशासनिक फेरबदल के तहत नई नियुक्तियां की गई हैं।

विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार अधिकारियों की नई नियुक्तियां

7-बटाला विधानसभा क्षेत्र: इस हलके के लिए कमिश्नर, नगर निगम बटाला को नया चुनाव पंजीकरण अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

8-श्री हरगोबिंदपुर (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र : इस आरक्षित हलके के लिए उप मंडल मजिस्ट्रेट बटाला को चुनाव पंजीकरण अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

10-डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र: हलके के लिए नायब तहसीलदार कलानौर को सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी-I/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर-I के रूप में नियुक्त किया गया है।

पोर्टल अपडेट करने और चुनावी कार्यों को समय पर पूरा करने की कड़ी हिदायतछ

जिला चुनाव अधिकारी आदित्य उप्पल ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे बिना किसी देरी के तुरंत अपने क्रेडेंशियल्स और विवरण पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान में चल रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन सहित चुनाव से जुड़े अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी निष्ठा के साथ मुकम्मल किया जाए।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 1,00,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सब-इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ़
18 जून (शैली अल्बर्ट)

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अपनी मुहिम के दौरान एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, जालंधर में तैनात सब-इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह को 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आज यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव गोहावर, थाना गोराया, जिला जालंधर की निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है और उक्त एसआई अमनदीप सिंह इस मामले में उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी फंसाने तथा उनकी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकियां दे रहा था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी एसआई पहले ही उससे अलग-अलग मौकों पर 6.50 लाख रुपये रिश्वत के रूप में ले चुका है और उसकी भाभी को मामले में नामजद होने से बचाने के लिए 2 लाख रुपये और मांग रहा था। शिकायतकर्ता ने उक्त पुलिस कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने की बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली थी। और रिश्वत देने के लिए तैयार न होने पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो यूनिट कपूरथला से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी एसआई को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।

कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल मनिंदर सिंह, जो आरोपी एसआई के साथ था, वाहन सहित मौके से फरार हो गया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो के थाना जालंधर में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

पावन तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए गांव उदोवाली खुर्द से बस रवाना

» प्रथम न्यूज । गुरदासपुर
18 जून (संदीप सन्नी)

डेरा बाबा नानक से विधायक गुरदीप सिंह रंधावा द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत गांव उदोवाली खुर्द से पवित्र धरती श्री आनंदपुर साहिब के लिए श्रद्धालुओं की एक विशेष बस को रवाना किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दीं और उनकी सुखद, मंगलमय तथा सफल यात्रा की कामना की।

इस मौके पर संगत से बातचीत करते हुए विधायक रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया यह अनूठा प्रयास हमारे बुजुर्गों और संगत को अपने गौरवशाली ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरसे के साथ जोड़ने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और परमात्मा से उनकी धार्मिक यात्रा के सुखद और सफल होने की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने जताया मुख्यमंत्री और विधायक का आभार। इस पावन यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायक रंधावा का विशेष रूप से धन्यवाद किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के कारण पूरे इलाके के लोगों में भारी खुशी का माहौल है और वे अपने पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

तीन दिनों में इन पवित्र स्थलों के होंगे दर्शन

विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बस के माध्यम से श्रद्धालुओं को तीन दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे।

- **श्री आनंदपुर साहिब तख्त**
- **श्री केसगढ़ साहिब विरासत-ए-खालसा**
- **श्री कीरतपुर साहिब**
- **माता नैना देवी जी**

बीएलओ ड्यूटी निभा रहे शिक्षकों के तबादलों पर रोक तानाशाही: जीटीयू पंजाब

यूनियन ने कहा- चुनावी कार्य के बदले शिक्षकों को सजा देना उचित नहीं, सरकार और शिक्षा विभाग से मांगा स्पष्टीकरण

» प्रथम न्यूज । जालंधर/फगवाड़ा
18 जून (शिव कुमार)

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (जीटीयू) पंजाब ने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत शिक्षकों के तबादलों पर 1 अक्टूबर 2026 तक लगाई गई रोक का कड़ा विरोध किया है। यूनियन नेताओं ने इसे सरकार और चुनाव आयोग की तानाशाही करार देते हुए कहा कि इससे लंबे समय से अपने घरों से दूर कार्यरत शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है।

यूनियन के सहायक प्रेस सचिव गणेश भगत, जिला कपूरथला के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह सैणी तथा तहसील फगवाड़ा के प्रधान परमजीत चौहान ने जारी बयान में कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब द्वारा 16 जून 2026 को जारी पत्र के अनुसार एसआईआर-2026 के दौरान नियुक्त बीएलओ और सुपरवाइजरों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग शिक्षकों से चुनावी कार्य करवा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी कार्य के कारण उनके तबादलों पर रोक लगाकर उन्हें सजा दी जा रही है।

यूनियन नेताओं ने कहा कि शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया पहले ही तकनीकी खामियों, न्यायालयी मामलों, गलत डेटा अपलोड होने और ट्रांसफर पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के कारण विवादों में घिरी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग के नए निर्देशों ने शिक्षकों के बीच और अधिक असमंजस तथा भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 8 जून 2026 तक नियुक्त बीएलओ की सूची आयोग को भेजी

जा चुकी है और उनके नाम गणना प्रपत्रों पर भी दर्ज किए जा चुके हैं। इसलिए आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बीएलओ का तबादला नहीं किया जा सकता। साथ ही, यदि किसी बीएलओ का तबादला सूची

अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया गया है तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जीटीयू नेताओं ने मांग की कि शिक्षा विभाग तुरंत स्पष्ट करे कि बीएलओ ड्यूटी निभा रहे शिक्षकों के तबादलों

के संबंध में क्या नीति अपनाई जाएगी। उनका कहना है कि यदि चुनाव आयोग के निर्देशों के कारण ऐसे शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगनी थी तो इसकी जानकारी पहले ही सार्वजनिक की जानी चाहिए थी, ताकि शिक्षक अनावश्यक मानसिक तनाव और परेशानी से बच सकें।

यूनियन ने सुझाव दिया कि यदि किसी बीएलओ शिक्षक का तबादला हो जाता है तो उसे नए स्टेशन पर जॉइन करवाकर एसआईआर कार्य की अवधि तक उसकी ड्यूटी पुराने स्कूल में ही जारी रखी जाए। एसआईआर का कार्य पूरा होने के बाद उसे नए स्थान पर नियमित रूप से कार्यभार संभालने दिया जाए। इससे तबादला प्रक्रिया से जुड़े विवादों और तकनीकी समस्याओं का समाधान भी संभव हो सकेगा।

यूनियन नेताओं ने सरकार और शिक्षा विभाग से शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी, स्पष्ट और एक समान दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की, ताकि तबादला प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विवाद रहित ढंग से पूरी की जा सके।

प्रथम न्यूज़
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
हिमाचल न्यूज़
Website : www.prathamnews.in

संक्षिप्त न्यूज

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कल्याण कार्यालय में दिलाई गई नशामुक्ति की शपथ

चम्बा (एएम नाथ): भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला कल्याण कार्यालय, चम्बा द्वारा नशा उन्मूलन एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने की। इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु शपथ दिलाई गई।

इस दौरान जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार एवं समाज के लिए गंभीर चुनौती है। स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण के लिए सभी को नशे से दूर रहना चाहिए तथा युवाओं को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ समाज में भी नशामुक्ति का संदेश प्रसारित करने का आह्वान किया। इस दौरान सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वे किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे तथा समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथ ही युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने का भी संकल्प लिया गया।

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने तथा नशे के विरुद्ध सामाजिक चेतना को सुदृढ़ करने के लिए जिला कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहेगा।

26 जून को मनाया जाएगा एंटी चिट्टा दिवस

चम्बा (एएम नाथ): प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आगामी 26 जून को जिला भर में एंटी चिट्टा दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान जिला, उपमंडल तथा पंचायत स्तर पर समाज को नशामुक्त एवं चिट्टा मुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने आज एंटी चिट्टा अभियान के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा समाज में नशे के खिलाफ जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 26 जून को सुबह सभी विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में और सरकारी कार्यालयों में प्रात: 11 बजे एंटी चिट्टा शपथ ग्रहण की जाएगी। वहीं पंचायत स्तर में भी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस विषय में उपमंडल अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिले में संचालित एंटी-चिट्टा अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, युवा मंडलों एवं महिला मंडलों से सक्रिय एवं बढ़-चढ़कर सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ प्रभावी जनजागरूकता पैदा करने में इन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी, सहायक आयुक्त मनमोहन सिंह, एसडीएम चम्बा प्रियांशु खाती, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जालम सिंह भारद्वाज, जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर, ओएसडी (शिक्षा) उमाकांत, सहायक अभियंता जल शक्ति दीपक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न उपमंडलों के उपमंडलाधिकारी (नागरिक) एवं तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

30-35 वर्षों पुरानी भनौता बस सेवा बंद, ग्रामीणों में बढ़ा रोष

चम्बा (एएम नाथ): ग्राम पंचायत भनौता एवं चनेड के लिए पिछले 30-35 वर्षों से संचालित हो रही HRTC की भनौता बस सेवा पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है। बस सेवा के बंद होने से क्षेत्र की महिलाओं, स्कूल एवं कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों तथा सुबह जल्दी नौकरी के लिए आने-जाने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बस सेवा के बंद होने से उन्हें निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे यात्रा खर्च भी बढ़ गया है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और विद्यार्थियों को नियमित परिवहन सुविधा न मिलने से परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने दोनों पंचायतों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे HRTC प्रबंधन से बातचीत कर इस बस सेवा को शीघ्र पुन: बहाल करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। ग्रामीणों का कहना है कि बस सेवा केवल बहाल ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे प्रतिदिन नियमित रूप से संचालित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को स्थायी राहत मिल सके। ग्राम पंचायत भनौता के काली माता महिला मंडल के सदस्यों तथा शिव मंदिर कमेटी भनौता के प्रधान ने भी HRTC से जल्द बस सेवा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकारी बस सेवा उपलब्ध होने से महिलाओं, विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को सरकार द्वारा निर्धारित किराया रियायतों का लाभ मिल सकेगा, जिससे आर्थिक बोझ भी कम होगा। स्थानीय निवासी विकास शर्मा नुहाल, मंजीत ठाकुर, मनीष शर्मा, डिम्पल चौहान, राधा शर्मा, सपना शर्मा, सुरजीत कुमार व मुस्कान ठाकुर ने बताया कि यदि इस मार्ग पर सरकारी बस सेवा की शीघ्र बहाली नहीं की गई तो क्षेत्रवासी सामूहिक रूप से जिलाधीश चंबा को प्रार्थना पत्र सौंपकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि HRTC और प्रशासन जनहित को देखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर बस सेवा को पुन: सुचारू रूप से शुरू करेंगे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई शपथ

पारदर्शिता और जनभागीदारी से गांवों के विकास का किया आह्वान, अगले पांच वर्षों में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य - मुख्यमंत्री

» प्रथम न्यूज । धर्मशाला
18 जून (बी.शर्मा)

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कांगड़ा जिले के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। धर्मशाला के दाड़ी मैदान में आयोजित समारोह में उन्होंने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए पंचायतों को लोकतंत्र की सबसे सशक्त इकाई बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने तथा नशे के खिलाफ जन आंदोलन को मजबूत करने का सामूहिक संकल्प भी दिलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं तथा गांवों के विकास, सामाजिक समरसता, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया है तथा ग्रीन बोनस, भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड, शानन परियोजना और अन्य मुद्दों पर हिमाचल के अधिकारों की मजबूती से पैरवी की जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि अगले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेगा।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दूध, हल्दी, गेहूं, मक्का और अदरक पर बढ़ाए गए समर्थन मूल्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए शीघ्र ही पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी।

नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपनी पंचायतों को चिट्टा मुक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जा रहे हैं तथा कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ जनसेवा को प्राथमिकता देंगे और आदर्श पंचायतों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

धर्मशाला को मिली बड़ी सौगात

CM सुक्खू ने 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास

» प्रथम न्यूज । धर्मशाला
18 जून (एएम नाथ)

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को धर्मशाला स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में निर्मित होने वाले 50 बिस्तरों की क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय कर समग्र एवं एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इस नए अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी तथा लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों से युक्त एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक किशोरी लाल, मलेंद्र राजन तथा कमलेश ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का लोकार्पण : इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के चरान में स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डीएससीएल) द्वारा 7.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शापिंग काम्प्लेक्स एवं मनोरंजन केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को खरीदारी, मनोरंजन तथा दैनिक उपयोग से जुड़ी अन्य आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी।

आय के नए अवसर सृजित होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र के आरंभ होने से क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे आसपास के दुकानदारों एवं लघु उद्यमियों के लिए व्यापार एवं आय के नए अवसर सृजित होंगे और उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

धर्मशाला में शपथ से पहले सियासी संग्राम

सीएम सुक्खू का पुतला फूंकने पर भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज

धर्मशाला (एएम नाथ)- धर्मशाला में शपथ से पहले नगर निगम भाजपा पार्षदों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिस कार्यालय में शपथ लेने व लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचना था। वहां पर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू व नगर निगम के आयुक्त का विरोध जताने पहुंचे पार्षदों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

धर्मशाला पुलिस ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का पुतला फूंकने के आरोप में आठ से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों व पार्षदों पर मामले दर्ज किए हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नगर निगम कार्यालय के बाहर वीरवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया, नारेबाजी की और पुतला फूंकने में भी सफल रहे। हालांकि, इस बीच कुछ समय के लिए पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही, जब पुतलों को आग लग गई तो जलते हुए पुतले पुलिस कर्मी ने छीनते हुए आगे नाले की तरफ फैंक दिए। इस बीच पुलिस की भी काफी फजीहत हुई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना जमकर आक्रोश भी दिखाया। नगर निगम धर्मशाला चुनाव 17 मई को हुए और परिणाम 31 मई को घोषित हुए। लेकिन नवनिर्वाचित पार्षदों की शपथ अब तक नहीं हो पाई है। शपथ में देरी से नाराज भाजपा समर्थित पार्षदों ने वीरवार को स्मृद्धि भवन के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों का कहना है कि शपथ न होने से वार्ड की समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं और जनता को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। कोतवाली बाजार के फव्वारा चौक पुनर्विकास के विधायक निधि से कराए गए कार्य का उद्घाटन मुख्यमंत्री के नाम की पट्टिका लगाकर किया गया। इस मौके पर प्रदर्शन में भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष भवनेश चौधरी, प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु सहित भाजपा पार्षद व कार्यकर्ता मौजूद थे। एसएचओ धर्मशाला नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है।

मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित : सुरेश चंदेल

21 जून को पंचायत स्तर पर योग दिवस, 25 जून को काला दिवस और 28 जून को बूथों पर होगी मन की बात : भाजपा

भाजपा का जनसंपर्क अभियान तेज, बालूगंज में घर-घर पहुंचाकर गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां

» प्रथम न्यूज । शिमला
18 जून (बी.शर्मा)

भाजपा जिला शिमला की मासिक बैठक का आयोजन दीपकमल, चक्कर में किया गया। बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा जिला प्रभारी सुरेश चंदेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे जनसंपर्क अभियानों की समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए सुरेश चंदेल ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है केवल एक नारा नहीं बल्कि पिछले 12 वर्षों में देश में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने, 81 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन उपलब्ध करवाने, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान देने तथा 60 करोड़ से अधिक लोगों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है।

सुरेश चंदेल ने बताया कि भाजपा द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पंचायत स्तर पर मनाया जाएगा। 25 जून को आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाकर लोकतंत्र पर हुए सबसे बड़े हमले को याद किया जाएगा। वहीं 28 जून को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुनेंगे। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान, जनसंपर्क अभियान, पौधारोपण अभियान एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

बैठक के उपरांत बालूगंज क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने 25 घरों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक वितरित किए।

कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई तथा सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक ले जाने का कार्य किया।

इस अवसर पर कुसुम सदरेट, नितिन कुमार, केशव चौहान, सुरेश भारद्वाज, संजय सूद, रवि मेहता, कमलजीत सूद, गणेश दत्त, रमा ठाकुर, कर्ण नंदा, शिवानी, अक्षय भरमौरी, प्यार सिंह कंवर, प्रमोद ठाकुर, प्रेम ठाकुर, विजय परमार, निखिल ठाकुर, राजीव पंडित, योग राज सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रथम न्यूज़
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
हरियाणा न्यूज़
Website : www.prathamnews.in

संक्षिप्त न्यूज

राज्य स्तरीय गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी समारोह के लिए हरियाणा सरकार का जताया आभार

चंडीगढ़, (मुकेश डोलिया): हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGPC) के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर मनाए गए गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के लिए कमेटी और हरियाणा की सिख संगत ने मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद किया।

?हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने और राज्य स्तरीय शहीदी समारोह के लिए हरियाणा सरकार का जताया आभार

?चंडीगढ़ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य स्तर पर धन-धन श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसके लिए पूरी हरियाणा की सिख संगत सरकार की आभारी है.अध्यक्ष ने सरकार के उस फैसले का भी पुरजोर स्वागत किया जिसके तहत आठवीं कक्षा और उससे ऊपर की इतिहास की किताबों में सिख गुरु साहिबान और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के गौरवमयी इतिहास को शामिल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों और फैसलों से आने वाली नई पीढ़ी को अपने महान इतिहास और शहीदों की कुर्बानियों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे समाज में आपसी भाईचारा और मजबूत होगा. इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच चल रहे विवाद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख कौम की सर्वोच्च और सबसे सम्मानित संस्था है. उन्होंने कहा कि वे इस पवित्र संस्था के खिलाफ किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी का कड़ा विरोध करते हैं.

कोर्ट केसों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई : विश्राम कुमार मीणा

कुरुक्षेत्र,18 जून(बृज मोहन) उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कोर्ट केसों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस समय अदालत में लंबित केसों में जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई पूरी की जाए, इसके लिए अधिकारियों को एक महीने का समय दिया गया है। इसके लिए बकायदा सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किए गए है।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा लघु सचिवालय के सभागार में लंबित कोर्ट केसों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लम्बित केसों को लेकर ऑनलाइन प्रणाली से एसडीएम पिहोवा अनिल दून, एसडीएम शाहबाद शम्भू राठी सहित इस्माईलाबाद व लाडवा के राजस्व विभाग के अधिकारियों से फीडबैक ली और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी कार्य प्रणाली में और सुधार करना होगा तथा अदालत में लंबित केसों पर गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी।

उपायुक्त ने बकायदा सरकार के आदेशों को सभी अधिकारियों के समक्ष रखा और कहा कि सालों साल जवाब का इंतजार नहीं किया जाएगा। इस विषय में सरकार ने कडा रुख अपनाया है और निर्णय लिया है कि कोर्ट में कोई भी केस अधिकारी की लापरवाही के कारण लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी और जल्द से जल्द तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना होगा ताकि केसों का निपटारा संभव हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी एक्शन टेकन रिपोर्ट को जरूर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम अमन कुमार, डीआरओ चेतना चौधरी सहित आदि अधिकारी उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में नहीं रहनी चाहिए किसी प्रकार की कमी-विश्राम कुमार मीणा

कुरुक्षेत्र, 18 जून (बृज मोहन) उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में किया जाएगा। इस योग दिवस को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी समय रहते तैयारियां पूरी करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।इससे पहले जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. मंजू शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों की रूप रेखा अधिकारियों के समक्ष रखी और विभाग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी है।

उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में 21 जून को जिला स्तरीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। योग शिविर का प्रशिक्षण भी ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में सांसद,विधायक, भाजपा नेता, अधिकारी व कर्मचारियों के साथ साथ आमजन भी भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आयुष विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, पंचायत विभाग, नगरपरिषद व नगरपालिकाएं, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग,आईटीआई सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी पूरा सहयोग देंगे ताकि जिला स्तरीय योग दिवस को सफल बनाया जा सके।

इस मौके पर एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम अमन कुमार, नगराधीश आशीष कुमार, डीआरओ चेतना चौधरी सहित आदि अधिकारी उपस्थित थे।

श्री गुरु अर्जन देव जी का बलिदान सत्य, साहस और मानवता की रक्षा का अमर संदेश : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा सरकार सिख गुरुओं के इतिहास और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ़

18 जून (मुकेश डोलिया)

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का बलिदान भारतीय इतिहास में सत्य, धर्म, मानवता और आध्यात्मिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उनका जीवन और शहादत हमें अन्याय, अत्याचार और असत्य के सामने कभी न झुकने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को पंचकूला में श्री गुरु अर्जन देव जी के 420वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छबील सेवा भी की। कार्यक्रम में हरियाणा व पंजाब से अनेक संत-महापुरुष पहुंचे और हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।

हरियाणा सरकार द्वारा 'संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना' के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री माता मनसा देवी और श्री नाडा साहिब की पावन धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान केवल सिख समाज की धरोहर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक पराक्रम की गौरवशाली परंपरा से भरा हुआ है। जब-जब देश, धर्म, संस्कृति और मानवता पर संकट आया, तब-तब हमारे गुरुओं और संतों ने अपने बलिदान से सत्य और धर्म की रक्षा की। श्री गुरु अर्जन देव जी का बलिदान इसी महान परंपरा का सर्वोच्च उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने समाज को जोड़ने और मानवता को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया। उन्होंने अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना कर उसके चारों दिशाओं में चार द्वार बनवाए, जो इस बात का प्रतीक हैं कि यह पवित्र स्थान किसी एक जाति, वर्ग या धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए खुला है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने सदियों पहले ही सामाजिक समरसता, समानता और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को साकार रूप दिया।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरुग्रंथ साहिब में संत कबीर, संत नामदेव, बाबा फरीद और संत रविदास सहित विभिन्न संतों की वाणी को संकलित कर गुरु अर्जन देव जी ने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का अनुपम कार्य किया। गुरु ग्रंथ साहिब आज भी पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में मार्गदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदी दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि जब हम श्री गुरु अर्जन देव जी के बलिदान को याद करते हैं तो गौरव के साथ-साथ उन यातनाओं का स्मरण भी होता है, जिन्हें उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा

के लिए सहन किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर की सत्ता गुरु साहिब के बढ़ते प्रभाव और आध्यात्मिक जागरण से भयभीत हो गई थी। उन्हें लाहौर में बंदी बनाकर अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तपती तवी पर बैठाना, शरीर पर गर्म रेत डालना और असहनीय पीड़ा देना अत्याचार की पराकाष्ठा थी, लेकिन गुरु साहिब के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने 'तेरा किया मीठा लागे' का उच्चारण करते हुए परमात्मा की इच्छा को स्वीकार किया। यह घटना केवल शहादत नहीं बल्कि आध्यात्मिक धैर्य, आत्मबल और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु अर्जन देव जी का बलिदान हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और संस्कृति की रक्षा के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब गुरु साहिब की शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक शक्ति हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की धरती संतों, गुरुओं और वीरों की भूमि रही है। यहां की मिट्टी में गीता का ज्ञान भी है और गुरुओं के बलिदानों की सुगंध भी। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सिख गुरुओं के योगदान और बलिदान को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, वीर बाल दिवस का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन तथा करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण इसी दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी सिख इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हरियाणा सरकार ने आठवीं कक्षा के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया है। अब विद्यार्थी सिख गुरुओं के साथ-साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर के त्याग, बलिदान और आदर्शों का भी अध्ययन करेंगे। उन्होंने बताया कि श्री हजूर साहिब, नांदेड़ की यात्रा के लिए कुरुक्षेत्र और सिरसा से विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया गया। इसके अलावा वर्ष 1984 के दंगा प्रभावित 121 परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। वीर बाल दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पंचकूला में इन परिवारों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की लगभग नौ एकड़ भूमि बिना किसी शुल्क के गुरुद्वारा साहिब के नाम हस्तांतरित की गई है। उन्होंने स्वयं संगत की उपस्थिति में इसके दस्तावेज सौंपे थे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इसी प्रकार अंबाला के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और टोहाना-जींद-धमतान साहिब मार्ग का नामकरण भी गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में किया गया है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिख गुरुओं ने समानता, सेवा, करुणा, भाईचारे और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। प्रधानमंत्री का 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र भी इसी भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा कि गुरुओं द्वारा शुरू की गई लंगर परंपरा हमें समानता और मानवता का संदेश देती है। यह व्यवस्था सिखाती है कि राजा और रंक, अमीर और गरीब सभी समान हैं। समाज से जात-पात, छुआछूत और भेदभाव को समाप्त कर एक समरस और सशक्त समाज का निर्माण करना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास और बलिदानों से प्रेरणा लें। जब युवा अपने इतिहास और विरासत को जानेंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी योगदान दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरु अर्जन देव जी के बताए सत्य, सेवा, करुणा और सिमरन के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यही गुरु साहिब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का सबसे प्रभावी मार्ग है। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार जगदीश सिंह झींडा, बडखल विधायक धनेश अदलखा, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन सिंह, ज्ञानी हरप्रीत सिंह, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष स. गुरमीत सिंह, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता, संत बाबा जोगा सिंह, सरदार जसदीप सिंह, महंत महेश मुनि, संत बाबा मान सिंह जुरासी वाले, स्वामी राजेश्वरानंद, बाबा सुल्तान सिंह व बाबा देवेंद्र सिंह इसराना सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ी का एक्सिडेंट, फिर हथियार छीन भागे शूटर

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ़

18 जून (पुनीत महाजन)

चंडीगढ़ पुलिस को सेक्टर-11 स्थित केमिस्ट शॉप के कैशियर हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात में शामिल दो आरोपियों सन्नी मेहरा (22) और आर्यन शर्मा (21) को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी जम्मू के निवासी हैं। गुरुवार तड़के चंडीगढ़ लाते समय धनास जंगल के पास पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिए और भागने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग भी की।

चंडीगढ़ पुलिस के आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों को रोकने के लिए पहले चेतावनी दी गई, लेकिन वे नहीं रुके। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चार राउंड फायरिंग की। कुल छह राउंड गोलियां चलीं। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में वाहन चालक भी घायल हुआ है। आईजी के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी बस से दिल्ली और फिर ट्रेन के जरिए जम्मू-कश्मीर पहुंचे थे। मामले

की जांच के लिए गठित एसआईटी में स्थानीय थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच, ऑपरेशन सेल और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल को शामिल किया गया था। प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, हालांकि उनके कुछ संपर्क आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से रहे हैं। पुलिस उनके पारिवारिक और सामाजिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

आईजी ने बताया कि हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार अभी बरामद नहीं हुए हैं। हथियार तीसरे आरोपी अमित के पास होने की आशंका है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जांच एजेंसियां फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और पूरे मॉड्यूल की भी पड़ताल कर रही हैं।

हिमाचल की महिला प्रधान के पति के 2 हत्यारों का एनकाउंटर

भागने की कोशिश में दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, जम्मू से लाए जा रहे थे आरोपी, धनास में हादसे के बाद हुआ एनकाउंटर

» प्रथम न्यूज । चंडीगढ़

18 जून (पुनीत महाजन)

सेक्टर-11 स्थित कुमार मेडिकल स्टोर के कैशियर हिमाचल की महिला प्रधान के पति जानकी दास हत्याकांड में गिरफ्तार दो आरोपियों को चंडीगढ़ लाते समय पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए सेक्टर 16 में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी देगी।

पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन सेल की क्राइम ब्रांच ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहयोग से हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों सनी और आर्यन को राजौरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। दोनों को बुधवार देर रात जम्मू से चंडीगढ़ लाया जा रहा था। इसी दौरान धनास के पास पुलिस वाहन चालक को झपकी आने से गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। हादसे का फायदा उठाकर वाहन में पीछे बैठे दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने।

पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने एक कांस्टेबल से पिस्तौल छीन ली और फायरिंग कर दी। इस दौरान एक आरोपी ने जांच टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर पर भी गोली चलाई, हालांकि वह बाल-

बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें काबू कर लिया। जांच में सामने आया है कि हत्याकांड में कुल तीन आरोपी शामिल थे। दो आरोपियों ने जानकी दास पर गोलियां चलाई थीं, जबकि तीसरा आरोपी बाइक पर इंतजार कर रहा था। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी सेक्टर-52 क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़े बदले और ऑटो के जरिए सेक्टर-43 बस अड्डे पहुंचे। वहां से वे बस से दिल्ली और बाद में ट्रेन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वारदात में गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। उसके ट्राईसिटी क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले हैं और उसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

वहीं, मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के पांच कर्मियों, जिनमें तीन महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, को निलंबित किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एंटी नारकोटिक सैल-टू द्वारा 267 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) सहित आरोपी काबू, बाइक जब्त

आरोपी का 5 दिन पुलिस रिमांड हासिल

» प्रथम न्यूज । कैथल

18 जून (कृष्ण गर्ग)

जिला पुलिस द्वारा आईजी करनाल रेंज करनाल अशोक कुमार के आदेशानुसार एसपी मनप्रीत सिंह सूदन कुशल नेतृत्व में नशा मुक्त हो जिला अभियान तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक एंटी नारकोटिक सैल-टू को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर क्षेत्र से एक आरोपी को 267 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) सहित गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 7 लाख रुपये आंकी गई है। डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक सैल-टू प्रभारी पीएसआई सनेश कुमार की टीम अपराध की रोकथाम हेतु गश्त पर संगतपुरा क्षेत्र में मौजूद थी। पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना

प्राप्त हुई कि बरनाला पंजाब निवासी जगदीप उर्फ जग्गी हेरोइन (चिट्टा) का नशा करने व बेचने का कार्य करता है और जो अभी अपनी डिलक्स पंजाब नंबर बाइक पर सवार होकर पंजाब से संगतपुरा इसी रास्ते होते हुए कैथल की तरफ जाएगा। जिसे नाकाबंदी करके काबू किया जा सकता है।

सूचना को पुख्ता मानते हुए टीम ने तुरंत रेडिंग पार्टी गठित कर रजबाहा पुल संगतपुरा पर नाकाबंदी शुरू की गई। कुछ समय बाद गांव बरटा की तरफ रजबाहे के साथ लगते रास्ते से एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकने का इशारा दिया गया। लेकिन संदिग्ध युवक पुलिस टीम को देखकर बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे टीम ने तत्परता से काबू कर लिया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान बरनाला पंजाब निवासी जगदीप उर्फ जग्गी के रूप में बताई। पुलिस सूचना उपरांत मौके पर पहुंचे डीएसपी मुख्यालय कैथल बीर भान के समक्ष ली गई तलाशी के दौरान आरोपी की पैंट की जेब से एक पॉलीथिन से 267 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज करके मौके पर पहुंचे चौकी संगतपुरा प्रभारी पीएसआई मन्नु द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापक पूछताछ के लिए आरोपी का न्यायालय से 5 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।

प्रथम न्यूज़
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
संपादकीय
Website : www.prathamnews.in

आज का

संपादकीय

पहाड़ों की खामोश चीख

हिमाचल के पहाड़ विकास के साथ सुरक्षित परिवहन की भी मांग कर रहे हैं। हर बड़े हादसे के बाद केवल मुआवजा और जांच पर्याप्त नहीं हैं। मजबूत क्रैश बैरियर, बेहतर सड़क ढांचा और सख्त सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता बनाना होगा। वरना पहाड़ों की सड़कें यूं ही परिवारों की खुशियां निगलती रहेंगी और मातम की कहानियां दोहराती रहेंगी।

एएम नाथ

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे अब सामान्य खबर बनते जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी मानवीय त्रासदियां किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोर देने के लिए पर्याप्त हैं। चंबा जिले में मुंडन संस्कार से लौट रहे ग्रामीणों से भरी बोलेरो के गहरी खाई में गिरने से सात लोगों की मौत ने एक बार फिर पहाड़ी प्रदेश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह है कि मृतकों में तीन सगे भाई भी शामिल थे। एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र शोक और सदमे में डूब गया है।

हिमाचल में सड़क दुर्घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। हर वर्ष सैकड़ों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। हाल के वर्षों में कुल्लू, मंडी, किन्नौर, सिरमौर, शिमला और चंबा जैसे जिलों में कई बड़े हादसे हुए हैं। कहीं बसें गहरी खाइयों में गिरीं, कहीं निजी वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुए और कहीं ओवरलोडिंग तथा खराब सड़क परिस्थितियां मौत का कारण बनीं। बरसात के मौसम में स्थिति और भयावह हो जाती है, जब भूस्खलन, सड़क धंसने और दृश्यता कम होने जैसी समस्याएं दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ा देती हैं।

प्रश्न यह है कि आखिर इन हादसों के पीछे केवल चालक की गलती जिम्मेदार है या फिर व्यवस्था की भी बड़ी विफलता है? सच यह है कि हिमाचल की अधिकांश सड़कें आज भी सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। हजारों किलोमीटर लंबी पहाड़ी सड़कों के किनारे आज भी मजबूत क्रैश बैरियर नहीं हैं। जहां बैरियर लगे हैं, उनमें से कई जर्जर हो चुके हैं या उनकी गुणवत्ता ऐसी नहीं है कि वे किसी वाहन को गहरी खाई में गिरने से रोक सकें। अनेक स्थानों पर सड़कें बेहद संकरी हैं, मोड़ तीखे हैं और चेतावनी संकेत या रिफ्लेक्टर तक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

क्रैश बैरियर की समस्या विशेष रूप से गंभीर है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के एक ओर सैकड़ों फीट गहरी खाई होती है। ऐसी स्थिति में यदि वाहन थोड़ा भी अनियंत्रित हो जाए तो यात्रियों के बचने की संभावना बेहद कम रह जाती है। आधुनिक स्टील क्रैश बैरियर, वायर-रोप बैरियर और ऊर्जा अवशोषित करने वाली सुरक्षा प्रणालियां दुनिया के कई पर्वतीय क्षेत्रों में सफल साबित हुई हैं, लेकिन हिमाचल में इनका विस्तार अभी भी सीमित है। दुर्घटना के बाद जांच और मुआवजे की घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन हादसों को रोकने के लिए दीर्घकालिक निवेश और योजनाबद्ध कार्रवाई अक्सर दिखाई नहीं देती।

एक अन्य गंभीर समस्या सड़कों के रखरखाव की है। कई ग्रामीण संपर्क मार्ग वर्षों से मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गड्ढे, टूटे किनारे, अपर्याप्त जल निकासी और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र वाहन चालकों के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। पर्यटन सीजन में वाहनों का दबाव बढ़ जाता है, लेकिन सड़क ढांचा उसी अनुपात में विकसित नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाती है।

चालकों का प्रशिक्षण और यातायात अनुशासन भी चिंता का विषय है। कई मामलों में तेज गति, ओवरलोडिंग, थकान की स्थिति में वाहन चलाना और नियमों की अनदेखी हादसों को जन्म देती है। पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग के लिए विशेष कौशल और सावधानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस दिशा में व्यापक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव दिखाई देता है। साथ ही, कई ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच भी सीमित है, जिससे दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर में उपचार नहीं मिल पाता।

सरकार, प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को अब केवल दुर्घटनाओं पर शोक व्यक्त करने से आगे बढ़ना होगा। संवेदनशील और दुर्घटना-प्रवण स्थानों की वैज्ञानिक पहचान कर वहां उच्च गुणवत्ता वाले क्रैश बैरियर लगाए जाएं। सड़कों का नियमित सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य बनाया जाए। ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर तत्काल सुधार किया जाए। आधुनिक चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टिव मार्किंग, सीसीटीवी निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत किया जाए। साथ ही, चालक प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को भी व्यापक बनाया जाना चाहिए।

चंबा का यह हादसा केवल सात लोगों की मौत की खबर नहीं है। यह उस व्यवस्था की चेतावनी है जो वर्षों से सड़क सुरक्षा के मुद्दे को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे पाई। यदि अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ों की ये सड़कें विकास का मार्ग कम और मौत का रास्ता अधिक बनती जाएंगी। हिमाचल को ऐसी सड़क नीति की आवश्यकता है जिसमें हर नागरिक की सुरक्षित यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। आखिर किसी भी विकास का वास्तविक अर्थ तभी है जब लोग अपने घरों से निकलें और सुरक्षित वापस लौट सकें।

श्रम संहिताएँ लागू, पर श्रमिक सुरक्षा अब भी अधूरी

भारत में श्रम सुधारों को लंबे समय से आर्थिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता रहा है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करके चार नई श्रम संहिताएँ—वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ (ओएसएचडब्ल्यूसी) संहिता, 2020—लागू की हैं। हाल ही में इन संहिताओं के अंतर्गत नियमों की अधिसूचना के साथ इनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। सरकार का दावा है कि ये सुधार श्रम कानूनों को सरल बनाएंगे, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेंगे और श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे। हालांकि, ट्रेड यूनियनों, श्रम विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने इन संहिताओं में मौजूद कई कमियों तथा श्रमिक हितों की अपर्याप्त सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

विशाल कल्याण

भारत की श्रम कानून व्यवस्था लंबे समय से जटिल, बिखरी हुई और बहुस्तरीय रही है। विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के लिए अलग-अलग कानून होने के कारण नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए अनुपालन कठिन हो जाता था। चार श्रम संहिताओं का सबसे बड़ा उद्देश्य इसी जटिलता को समाप्त करना और एक एकीकृत कानूनी ढाँचा तैयार करना था। इन संहिताओं के पक्ष में सबसे प्रमुख तर्क यह है कि वे श्रम कानूनों को सरल बनाती हैं और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देती हैं। पहले जहाँ विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अलग-अलग पंजीकरण, रिजिस्टर और अनुपालन प्रक्रियाएँ थीं, वहीं अब एकीकृत व्यवस्था से प्रशासनिक बोझ कम होने की उम्मीद है। इससे उद्योगों को निवेश और विस्तार में सुविधा मिलेगी तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी के सार्वभौमिक विस्तार और समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

श्रम संहिताओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार है। भारत में करोड़ों श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ गिग और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। नई सामाजिक सुरक्षा संहिता इन श्रमिकों को पहली बार कानूनी रूप से मान्यता देती है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान करती है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो यह भारतीय श्रम बाजार में एक ऐतिहासिक परिवर्तन साबित हो सकता है।

हालांकि, इन सकारात्मक पहलुओं के बावजूद कई गंभीर चिंताएँ सामने आई हैं। सबसे अधिक विवाद निश्चित अवधि के रोजगार को लेकर है। संहिता में निश्चित अवधि के अनुबंधों को कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है और अनुबंधों के नवीनीकरण की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं है। इससे आशंका है कि नियोक्ता स्थायी नौकरियाँ देने के बजाय बार-बार अल्पकालिक अनुबंधों का उपयोग करेंगे। परिणामस्वरूप कर्मचारियों में नौकरी की असुरक्षा बढ़ सकती है और दीर्घकालिक रोजगार संबंध कमजोर हो सकते हैं। श्रमिक संगठनों का मानना है कि इससे स्थायी रोजगार की अवधारणा धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है।

वेतन निर्धारण के क्षेत्र में भी कई अस्पष्टताएँ बनी हुई हैं। न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम सीमा वेतन के बीच स्पष्ट अंतर का अभाव है। इसके अतिरिक्त वेतन निर्धारण के लिए पारदर्शी मानदंडों और राज्यों के साथ प्रभावी परामर्श तंत्र की कमी दिखाई देती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि मजदूरी निर्धारण वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित नहीं होगा, तो श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाएगा। विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों के श्रमिकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रति घंटा मजदूरी से संबंधित प्रावधान भी विवाद का विषय बने हुए हैं। वर्तमान श्रम बाजार में गिग कार्य, प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार और घरेलू कार्यों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे रोजगारों की प्रकृति पारंपरिक पूर्णकालिक नौकरियों से भिन्न होती है। यदि प्रति घंटा मजदूरी के लिए स्पष्ट और न्यायसंगत मानक विकसित नहीं किए गए, तो बड़ी संख्या में श्रमिक कम आय और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक भी इस क्षेत्र में अधिक स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर बल देते हैं।

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता है। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा संहिता इन श्रमिकों को मान्यता देती है, फिर भी उन्हें अभी भी स्व-नियोजित श्रमिकों के रूप में देखा जाता है। नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसके कारण प्लेटफॉर्म कंपनियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियाँ अस्पष्ट बनी हुई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद लाखों गिग श्रमिक स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सुरक्षा, पेंशन और अन्य सामाजिक लाभों से वंचित रह सकते हैं।

ग्रेच्युटी बीमा से संबंधित प्रावधानों में भी स्पष्टता का अभाव है। नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बीमा व्यवस्था कैसे लागू होगी, नियोक्ताओं की जिम्मेदारी क्या होगी और भुगतान न होने की स्थिति में श्रमिकों को क्या संरक्षण मिलेगा। इससे श्रमिकों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा उपाय कमजोर पड़ सकता है।

ट्रेड यूनियनों की भूमिका को लेकर भी अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। नई व्यवस्था में यूनियनों की मान्यता के लिए निर्धारित मानदंड छोटे और नए संगठनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इससे सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति कमजोर पड़ सकती है और श्रमिकों की आवाज प्रभावी ढंग से सामने नहीं आ पाएगी। औद्योगिक लोकतंत्र और श्रमिक भागीदारी के लिए मजबूत ट्रेड यूनियन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

संविदा श्रम के उपयोग को लेकर भी चिंताएँ बढ़ी हैं। ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता में मुख्य और गैर-मुख्य गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप स्थायी प्रकृति के कार्यों में भी संविदा श्रमिकों को नियुक्त किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे कार्यबल का अनौपचारिकीकरण बढ़ सकता है और श्रमिकों की सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, कई व्यवसाय-विशिष्ट कल्याणकारी प्रावधान भी नई संहिताओं में पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होते। उदाहरण के लिए, बागान श्रमिकों के लिए आवास और समर्पित चिकित्सा सुविधाओं जैसे प्रावधानों की अनुपस्थिति ने श्रमिक संगठनों को चिंतित किया है। इससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि श्रमिक कल्याण के स्थापित मानकों में धीरे-धीरे कमी आ सकती है।

इन चुनौतियों को देखते हुए आवश्यक है कि श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के दौरान श्रमिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। निश्चित अवधि के रोजगार के लिए न्यूनतम अनुबंध अवधि तय की जानी चाहिए और बार-बार नवीनीकरण पर सीमा लगाई जानी चाहिए। वेतन निर्धारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाया जाना चाहिए। गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्पष्ट सामाजिक सुरक्षा ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए।

संविदा श्रम के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए मुख्य और गैर-मुख्य गतिविधियों की स्पष्ट परिभाषा आवश्यक है। साथ ही, ट्रेड यूनियनों की भागीदारी को मजबूत करने, ग्रेच्युटी बीमा को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा व्यवसाय-विशिष्ट कल्याणकारी उपायों को संरक्षित रखने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

निष्कर्षतः

चार श्रम संहिताएँ भारत के श्रम सुधार इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। उन्होंने कानूनों के सरलीकरण, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और औद्योगिक दक्षता में सुधार की संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। किंतु केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये संहिताएँ श्रमिकों को कितनी प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती हैं और क्या वे आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित कर पाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, उद्योग और श्रमिक संगठनों के बीच निरंतर संवाद बना रहे, ताकि श्रम सुधारों का लाभ विकास और श्रमिक कल्याण दोनों को समान रूप से प्राप्त हो सके।

प्रतिगामी है जनसंख्या प्रोत्साहन नीति

हाल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की नई जनसंख्या प्रबंधन नीति के अंतर्गत तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में दूसरे बच्चे के जन्म पर पहले से ही 25 हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। ऐसे फैसलों के पीछे की वजह राज्य की गिरती 'कुल प्रजनन दर' और जनसांख्यिकीय असंतुलन की चुनौतियों से निपटना है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर देखें तो यह कदम लोकसभा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व घटने की आशंका और असुरक्षा की उपज है। संभव है कि जनसंख्या में संकुचन से जूझ रहे अन्य प्रदेश विशेषकर दक्षिणी राज्य भी आंध्र की यह राह पकड़ सकते हैं। ऐसा कोई प्रोत्साहन नितांत संकुचित सोच का ही परिणाम है, जिसमें राज्य के हित को राष्ट्र हित से ऊपर देखा जा रहा है। यह गिरती प्रजनन दर की सतही समझ और जनसांख्यिकीय असंतुलन के शार्टकट समाधान से अधिक कुछ नहीं है।

नायडू की गिनती प्रगतिशील नेताओं में होती है और अतीत में वे समेकित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने के पैरोकार भी रहे हैं, लेकिन उनका यह निर्णय प्रतिगामी है। यह राष्ट्रीय हितों के बरक्स वोट बैंक की राजनीति और प्रभावी दबाव समूह बने रहने की चाह का प्रतिफलन है।

नायडू का यह सोच उन वर्गों का हौसला ही बढ़ाएगा, जो अपनी संख्या से राजनीतिक वर्चस्व की चाह रखते हैं। अगर जनसंख्या में कमी को एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है तो फिर उसके उचित समाधान तलाशने होंगे। इसकी एक वजह बड़ी संख्या में युवाओं का समय पर विवाह न करना है। अगर देरी से विवाह हो भी जाए तो वे एक ही संतान को पर्याप्त समझने लगे हैं।

आज के प्रतिस्पर्धा से भरे जीवन और संयुक्त परिवारों के घटते चलन में बच्चों के पालन-पोषण की चुनौतियां कहीं अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे पहलुओं ने भी प्रजनन दर को प्रभावित किया है और एक हद तक इससे जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति भी निर्मित हो रही है। चूंकि भारत में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है तो घटती जनसंख्या वाले राज्यों को अपने राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी चिंता सता रही है। यह आशंका सिर्फ राज्यों की ही नहीं है, बल्कि तमाम धार्मिक और जातीय समुदायों में भी फैल रही है। ऐसी चिंताओं के बावजूद जनसंख्या बढ़ाने संबंधी प्रोत्साहन उचित नहीं, क्योंकि भारत में संसाधन और सुविधाएं सीमित हैं। इन सीमित संसाधनों पर पहले ही भारी जनसंख्या का दबाव है।

जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करें तो जनसंख्या और मानव संसाधन में अंतर होता है। कमाने वाले हाथों और आश्रितों के बीच सही संतुलन आवश्यक है। वर्तमान युग तो मशीन और तकनीक का है। इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्यधिक विकसित तकनीकी उपकरणों वाले युग में तो कमाने वाले हाथों को सोचने वाले मस्तिष्क ने काफी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है।

जनसंख्या को मानव संसाधन बनाने के लिए आधारभूत ढांचे, साधन-संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार, पेयजल, समुचित स्वास्थ्य, स्तरीय शिक्षा और कौशल विकास की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं द्वारा ही जनसंख्या को मानव संसाधन बनाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश की तो बात ही क्या, किसी विकसित देश में भी ये संसाधन और सुविधाएं असीमित नहीं।

कृषि भूमि और उसकी उत्पादन क्षमता, अन्यान्य प्राकृतिक संसाधन और यहां तक कि शुद्ध जल और वायु भी असीमित नहीं हैं। साधन-सुविधाओं के अभाव और बढ़ते अपराध के अंतर्संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, पर्यावरण असंतुलन और प्राकृतिक क्षरण के दुष्चक्र से हम सब अनभिज्ञ भी नहीं हैं।

तमाम सुविधाओं के अभाव और संसाधनों पर निरंतर बढ़ते दबाव ने न सिर्फ मानव-स्वभाव और चरित्र को विकृत किया है, बल्कि प्रकृति के स्वरूप को भी बदरंग और विध्वंसक बना डाला है। अत्यधिक दोहन और शोषण ने मनुष्य को प्रकृति का दुश्मन बना दिया है और यही कारण है कि नियमित अंतराल पर प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ी है। प्रख्यात अर्थशास्त्री माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण और प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्संबंध की विस्तृत विवेचना की ही है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रोत्साहन में कोई समझदारी नहीं, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश पहले ही चीन को पछाड़ कर पहले पायदान पर पहुंच गया है। भारत का जनसंख्या घनत्व भी चीन से लगभग तीन गुना अधिक है। इसलिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है कि समस्त देशवासी इस विकराल बन चुकी समस्या के बारे में सोचें और उसके समाधान की दिशा में सक्रिय हों। भौगोलिक क्षेत्रफल और अन्य संसाधनों-सुविधाओं और जनसंख्या में आनुपातिक संतुलन स्थापित करके ही राज्य अपने नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जो कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक कर्तव्य भी है। इन सुविधाओं से ही नागरिकों की गरिमा भी बहाल हो सकेगी। मानव जीवन का महत्व और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए समेकित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ही इस समस्या का समाधान निहित है।

राष्ट्र निर्माता के रूप में गृहणियों की भूमिका

वसुंधरा धर्माणी
घुमारवीं, बिलासपुर
हिमाचल प्रदेश

भारत में लंबे समय तक गृहणियों के कार्यों को केवल घरेलू जिम्मेदारी मानकर देखा जाता रहा है। परिवार की देखभाल, बच्चों का पालन- पोषण, बुजुर्गों की सेवा, घर का प्रबंधन, और संस्कारों का संवहन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने के बावजूद उनके श्रम को आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त मान्यता नहीं पाती। गृहिणी केवल घर संभालने वाली महिला नहीं होती, बल्कि वह परिवार रूपी संस्था की आधारशिला होती है। एक बच्चे के व्यक्तित्व, उसके संस्कार और भविष्य की नींव घर से ही पड़ती है। इस नींव को मजबूत बनाने में मां की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही बच्चे आगे चलकर देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, किसान और प्रशासक बनते हैं। इसके बावजूद उनके कार्यों को अक्सर आर्थिक दृष्टि से महत्व नहीं दिया गया और उन्हें केवल आश्रित मान लिया गया।

जून 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गृहणियों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गृहणियों के योगदान को राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माता कहना न केवल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन का भी संकेत है। यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह शामिल थे। दोनों न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गृहणियां केवल घर संभालने वाली महिलाएं नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं।

यह मामला वर्ष 2001 में पंजाब में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा था। दुर्घटना में रेशमा नामक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसके पति और बच्चों ने मुआवजे की मांग करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का दरवाजा खटखटाया। प्रारंभ में उन्हें बहुत कम मुआवजा मिला। बाद में मामला उच्च न्यायालय पहुंचा और अंततः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एक गृहिणी के योगदान को केवल इस आधार पर कम नहीं आंका जा सकता कि वह वेतन प्राप्त नहीं करती थी। न्यायालय ने माना कि घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, परिवार का प्रबंधन और भावनात्मक सहयोग जैसी जिम्मेदारियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनका आर्थिक मूल्य भी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने गृहणियों द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों के महत्व को स्वीकार करते हुए घरेलू देखभाल की हानि को मुआवजे का एक अलग आधार माना। इसके लिए न्यूनतम ?30,000 प्रति माह का मूल्य निर्धारित किया गया तथा यह भी कहा गया कि हर 3 वर्ष में इस राशि में 10त्न की वृद्धि की जानी चाहिए। यह राशि गृहणियों के पूरी तरह से योगदान का मूल्य नहीं है, बल्कि केवल मुआवजा निर्धारण के लिए एक न्यूनतम मानक है। वास्तव में एक गृहिणी का योगदान इससे कहीं अधिक व्यापक और अमूल्य है।

यह फैसला केवल मुआवजा की राशि तय करने तक सीमित नहीं है। इसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव हैं। यह निर्णय महिलाओं के आत्मसम्मान को मजबूत करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उनका योगदान समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सी महिलाएं स्वयं को केवल साधारण गृहिणी समझकर अपने योगदान को कम आंकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि गृहिणी होना कोई साधारण बात नहीं, बल्कि अत्यंत जिम्मेदारी और महत्व का कार्य है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन.कोटिश्वर सिंह द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय न्यायपालिका के संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचायक है। इस निर्णय ने करोड़ों गृहणियों के त्याग, परिश्रम और समर्पण को सम्मान प्रदान किया है। वास्तव में राष्ट्र का निर्माण केवल संसद या शासन चलाने से नहीं होता या बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने से नहीं होता, बल्कि उन घरों से होता है जहां एक मां अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, एक पत्नी परिवार को संभालती है और एक गृहिणी अपने प्रेम और श्रम से समाज की नींव को मजबूत करती है। आज समय की मांग है कि हम महिलाओं के कार्यों को केवल आर्थिक दृष्टि से ना देखें।

एक गृहिणी द्वारा दिया गया प्रेम, संस्कार और सुरक्षा किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। कमाने वाला ही परिवार का आधार है जैसी पुरानी सोच को बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि गृहणियां केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता हैं। यदि एक महिला घर की जिम्मेदारी निभा रही है तो वह केवल परिवार का ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य का निर्माण कर रही है।

प्रथम न्यूज़
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
हिमाचल न्यूज़
Website : www.prathamnews.in

संक्षिप्त न्यूज

बीडीओ ने स्कूली बच्चों को एंटी चिट्टा का शपथ दिलाई

पट्टा मेहलोग (तारा):राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटबेजा व राजकीय उच्च विद्यालय गुनाई में बीडीओ कुलदीप सिंह ने छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों व अन्य उपस्थित ग्रामीणों को चिट्टा के खिलाफ शपथ दिलाई। उन्होंने सभी को नशे के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि पाठशाला में एंटी चिट्टा बॉक्स में इस नशे से जुड़े लोगों की जानकारी लिख कर डाल दे ताकि इसका पूरे हिमाचल में खात्मा किया जा सके। उन्होंने एंटी चिट्टा अभियान को एक जन आंदोलन की तरह चलाने का आह्वान किया। पंचायत सचिव राज कुमार शर्मा ने भी बच्चों को नशे के खिलाफ जानकारी दी।

विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू बाला ने बताया कि एंटी चिट्टा अभियान पहली जून से 20 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थानों में चलाया जा रहा है। नीतू राय ने मंच का संचालन किया। एसएमसी प्रधान नरेश ठाकुर ने छात्रों को चिट्टे के खिलाफ अपने परिवार, दोस्तो व पड़ोसियों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया।

इस अभियान में विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा पाठशाला के प्रवक्ता सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, सरोज, उमा शंकर, ऋचा शर्मा, किरण पराशर, गोविंद राम और अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

कल्हेल हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे, किशोर समेत चार लोग निकले आरोपी

बैल्ट से पीटकर की हत्या, सबूत मिटाने को जलाई कमीज और बैल्ट

चुराह (चंबा) (एएम नाथ) - चंबा जिले के चुराह क्षेत्र के कल्हेल में हुए हरविंद्र सिंह हत्याकांड की जांच में पुलिस को कई सनसनीखेज तथ्य हाथ लगे हैं। इस निर्मम वारदात में तीन वयस्कों के साथ एक किशोर की संलिप्तता सामने आने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मामले ने समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों को लेकर भी गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। पुलिस जांच के अनुसार आरोपियों ने हरविंद्र सिंह को मौत के घाट उतारने से पहले बैल्ट से बेरहमी से पीटा था। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल की गई बैल्ट और मृतक की कमीज को जला दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जले हुए अवशेष बरामद कर लिए हैं, जिन्हें मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है।

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। इसके लिए हरविंद्र का शव कल्हेल पुल के समीप एक नाले में फेंक दिया गया ताकि लोगों को यह हादसा प्रतीत हो। लेकिन आरोपियों की एक बड़ी चूक ने पुलिस को मामले की तह तक पहुंचा दिया। मृतक का मोबाइल फोन, चार्जर और अन्य निजी सामान उस कमरे में ही छूट गया, जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। मामले की जांच जारी है।

मुंडन संस्कार से लौट रहा परिवार बना काल का ग्रास

पुखरी-मसरूंड मार्ग पर माणी जीरो (छतरूंड) के समीप अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो

चंबा में बोलेरो गहरी खाई में गिरी, 7 की मौत

» प्रथम न्यूज । चंबा

18 जून (एएम नाथ)

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में वीरवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। पुखरी-मसरूंड मार्ग पर माणी जीरो (छतरूंड) के समीप एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा।

हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार सभी सात लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बोलेरो (एचपी-01सी-2581) में ग्राम पंचायत महल के सपरोठ गांव के छह लोग सवार थे, जिनमें तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल थे। इनके अलावा

वाहन चालक भी गाड़ी में मौजूद था। बताया जा रहा है कि सभी लोग काकड़ोथा गांव में आयोजित एक मुंडन संस्कार समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार छतरूंड के समीप पहुंचने पर अचानक वाहन चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बोलेरो सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। वाहन कई सौ मीटर नीचे लुढ़कता चला गया, जिससे उसमें सवार किसी भी व्यक्ति को बचने का मौका नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया।

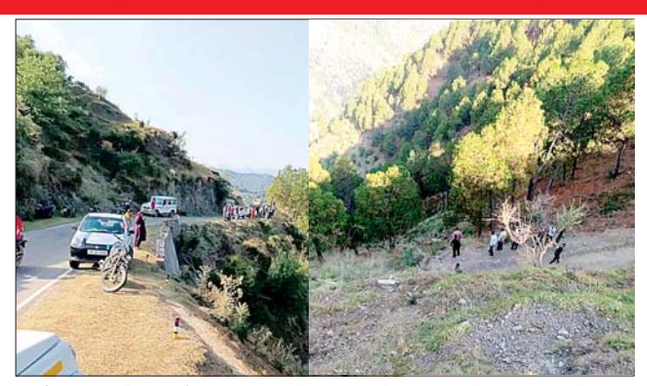

इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंचीं। दुर्घटनास्थल बेहद दुर्गम और गहरी खाई में होने के कारण बचाव अभियान चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को खाई से बाहर निकाला गया।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा।

सपरोठ पंचायत में मातम, मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

एक ही गांव और परिवार से जुड़े कई लोगों की मौत की खबर से सपरोठ पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संवेदनशील मार्गों पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन, प्रतिषेध एवं पुनर्वास को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

» प्रथम न्यूज । शिमला

18 जून (बी.शर्मा)

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन, प्रतिषेध एवं उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संबंधित प्रावधानों की समीक्षा के उद्देश्य से अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अधिनियम के तहत जिला में किए जा रहे कार्यों, सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई से जुड़े सुरक्षा मानकों तथा हाथ से मैला उठाने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभागों एवं स्थानीय निकायों को निर्देश दिए कि अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर हाथ से मैला उठाने जैसी अमानवीय प्रथा को बढ़ावा न मिलने पाए।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसे कर्मियों को सम्मानजनक जीवन एवं वैकल्पिक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए पुनर्वास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र व्यक्तियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से प्रदान किया जाए।

अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान मशीनों एवं सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए तथा श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जन-जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया ताकि समाज में इस कुप्रथा के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो सके।

जिला में अभी तक 22 जन-जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा सभी उपमंडल स्तर पर सतर्कता एवं प्रबोधन समिति का गठन किया जा चुका है।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अधिनियम के तहत की जा रही गतिविधियों एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।

बैठक में विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।

खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, शारीरिक दक्षता और खेल भावना का होता है विकास - संजय अवस्थी

ग्राम पंचायत दाड़लाघाट में दंगल आयोजित

» प्रथम न्यूज । सोलन

18 जून (बी.शर्मा)

अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में प्राचीन व आधुनिक खेल अहम भूमिका निभाते हैं। संजय अवस्थी गत देर सांय अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाड़लाघाट द्वारा आयोजित दंगल समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

संजय अवस्थी ने कहा कि प्राचीन खेल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। इन खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, शारीरिक दक्षता और खेल भावना का विकास होता है। उन्होंने युवाओं से पारंपरिक खेलों को अपनाने और इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने और नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाएं गए हैं। एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान ऐसा ही एक सकारात्मक कदम है। इस अभियान के तहत युवाओं को व्यवहारिक रूप से मादक पदार्थों के दूष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्हें खेलों व शारीरिक व्यायाम के प्रति आकर्षित किया जा रहा है ताकि वह नशे से दूर रहकर अपना भविष्य उज्जवल बना सके।

विधायक ने कहा कि क्षेत्रवासियों तक बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क नेटवर्क व अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में दाड़लाघाट अस्पताल में मेडिकल व पैरामेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च स्तर पर मामला उठाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि दाड़लाघाट में अर्की नागरिक अस्पताल की तर्ज पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की शीघ्र नियुक्ति की जाएगी।

संजय अवस्थी ने कहा कि खेल तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार योजनाबद्ध कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि दाड़लाघाट में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर लिया गया है तथा इसके निर्माण के लिए औपचारिकताएं अंतिम चरण में है।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अर्की विधानसभा क्षेत्र के दाड़लाघाट में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानें निर्मित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दाड़लाघाट में युवाओं के लिए पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा ताकि युवा वर्ग अपने भविष्य की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें।

उन्होंने दंगल समिति को 31 हजार रुपए देने की घोषणा की।

विधायक ने इस अवसर पर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ज़िला परिषद सदस्य दाड़लाघाट मीनाक्षी ठाकुर, ग्राम पंचायत दाड़लाघाट के प्रधान श्याम चौधरी, ग्राम पंचायत दाड़लाघाट के उप प्रधान हेमराज गौतम, ग्राम पंचायत बसंतपुर के उप प्रधान धनीराम, दी सोलन ज़िला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ सीमित के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, बाघल लैंड लूजर ट्रक ओपरेटर सोसायटी दाड़लाघाट के प्रधान जगदीश ठाकुर, अम्बुजा-दाड़ला-कसलोग-माँगू परिवहन सहकारी सभा सीमित दाड़लाघाट के प्रधान वेद प्रकाश शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के मोहन ठाकुर, राजेंद्र कंवर, नरेन्द्र सिंह चौधरी, मेला समिति के प्रधान सुरेन्द्र शुक्ला, जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता विवेक कटोच, तहसीलदार दाड़लाघाट प्रेमलाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे

भूमि एवं संपत्ति अधिकारों पर महिला आयोग चलाएगा जन जागरूकता शिविर - विद्या नेगी

कांगड़ा जिला में महिलाओं के भूमि अधिकारों पर अध्ययन में सामने आई असमानताए

» प्रथम न्यूज । शिमला

18 जून (बी.शर्मा)

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट (पीएमवीटी) द्वारा कांगड़ा जिला में महिलाओं के भूमि अधिकारों की स्थिति पर किए गए एक विस्तृत अध्ययन कर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज यहां आयोजित किया गया जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए विद्या नेगी ने कहा कि भूमि स्वामित्व महिलाओं को मिले इस दिशा में भविष्य में महिला आयोग जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित होंगे जिसमें विशेषज्ञ महिलाओं को एवं समाज के अन्य वर्गों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि और संपत्ति केवल आर्थिक संसाधन नहीं हैं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का आधार भी हैं। आज भी समाज में महिलाओं की भूमि एवं संपत्ति स्वामित्व में भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित है जबकि महिलाओं का परिवार, कृषि और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, फिर भी संपत्ति पर उनका अधिकार अक्सर कम दिखाई देता है।

महिलाओं को भूमि और संपत्ति का स्वामित्व मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है तथा परिवार और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ता है। शोध बताते हैं कि जिन महिलाओं के पास संपत्ति का स्वामित्व होता है, वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए अधिक प्रभावी निर्णय ले पाती हैं।

उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करें, उन्हें संपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित करें और सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाएं। बेटियों को भी परिवार की संपत्ति में समान अधिकार देना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहाँ महिलाओं को भूमि और संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त हो तथा वे आत्मविश्वास, सम्मान और स्वावलंबन के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी पूर्ण भागीदारी निभा सकें।

भूमि एवं संपत्ति अधिकारों में महिलाओं की भूमिका सीमित:पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा कांगड़ा जिले में महिलाओं के भूमि अधिकारों की स्थिति पर किए गए एक विस्तृत अध्ययन के अनुसार कानूनी प्रावधानों के बावजूद भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व, विरासत और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं के भूमि अधिकारों की वास्तविक स्थिति,

विरासत संबंधी प्रथाओं, कानूनी जागरूकता तथा सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच का आकलन करना था।

10 पंचायतों के 302 लोगों पर किया अध्ययन:अध्ययन के तहत कांगड़ा जिला की 10 पंचायतों में 302 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें 73 प्रतिशत महिलाएं थीं। सर्वेक्षण में 66 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे।

घरों का 76 फीसदी स्वामित्व पुरुषों के नाम:अध्ययन में पाया गया कि 76 प्रतिशत घरों का स्वामित्व पुरुषों के नाम पर है, जबकि केवल 18 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम दर्ज हैं। मात्र 6 प्रतिशत संपत्तियां संयुक्त स्वामित्व या अन्य श्रेणी में आती हैं। नई संपत्तियों की खरीद में भी पुरुषों की भागीदारी अधिक पाई गई, जहां 77 प्रतिशत खरीद पुरुषों द्वारा और केवल 17 प्रतिशत खरीद महिलाओं द्वारा की गई।

32 फीसदी लोगों ने माना पैतृक संपति पर पुत्र का हक:विरासत संबंधी धारणाओं में भी लैंगिक असमानता देखने को मिली। 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि पैतृक संपत्ति का मुख्य उत्तराधिकारी पुत्र होना चाहिए, जबकि केवल 13 प्रतिशत ने पुत्रियों को प्राथमिक उत्तराधिकारी माना। अध्ययन में यह भी सामने आया कि परिवार की 63 प्रतिशत संपत्ति पुरुष मुखियाओं के नाम पर है, जबकि विधवा महिलाओं के नाम पर 16 प्रतिशत संपत्ति दर्ज है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी पुरुषों का प्रभाव अधिक पाया गया। 37 प्रतिशत मामलों में पति को परिवार का प्रमुख निर्णयकर्ता माना गया, जबकि केवल 20 प्रतिशत मामलों में पत्नी की स्वतंत्र भूमिका सामने आई। शिक्षा एवं वित्तीय मामलों में संयुक्त निर्णय लेने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही।

सरकारी योजनाओं की वजह से महिलाओं को मिलते अधिक अधिकार

सरकारी योजनाओं की पहुंच के संबंध में अध्ययन में पाया गया कि राशन कार्ड, मनरेगा, जीवन बीमा तथा विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लाभार्थियों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में काफी अधिक रही, जो संपत्ति स्वामित्व में मौजूद लैंगिक अंतर को दर्शाता है।

67 फीसदी महिलाएं भूमि संबंधी दस्तावेजों को पढ़ने में सक्षम नह

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी रहा कि महिलाओं में भूमि अधिकारों संबंधी कानूनी जागरूकता का स्तर काफी कम है। 67 प्रतिशत महिलाएं भूमि संबंधी दस्तावेजों को पढ़ने और समझने में सक्षम नहीं पाई गईं, जबकि केवल 4 प्रतिशत महिलाओं ने कभी भूमि अधिकारों से संबंधित किसी जागरूकता शिविर में भाग लिया था।

दिव्यांगता और प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ी बाधा:अध्ययन के अनुसार महिलाओं द्वारा बताई गई प्रमुख बाधाओं में दिव्यांगता और प्राकृतिक आपदाएं सबसे अधिक रहीं। 26-26 उत्तरदाताओं ने इन्हें भूमि अधिकारों में बाधा बताया, जबकि 12 लोगों ने आर्थिक कठिनाइयों, 6 ने सामुदायिक दबाव, 5 ने जातिगत कारणों और एक उत्तरदाता ने लैंगिक भेदभाव को प्रमुख अवरोध बताया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कई बार लोग गहरे सामाजिक एवं संरचनात्मक कारणों की बजाय प्रत्यक्ष समस्याओं को ही बाधा मानते हैं, जबकि वास्तविक असमानताओं की जड़ें पारंपरिक विरासत व्यवस्था और सामाजिक मान्यताओं में निहित हैं। अध्ययन में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय की महिलाओं की स्थिति को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बताया गया है। सर्वेक्षण में शामिल 12 प्रतिशत एसटी महिलाओं में केवल 17 प्रतिशत के पास ही घर का स्वामित्व पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार एसटी महिलाएं दोहरी चुनौतियों का सामना करती हैं, क्योंकि वे न केवल मुख्यधारा के कानूनी सुरक्षा प्रावधानों से बाहर रह जाती हैं, बल्कि पारंपरिक व्यवस्थाओं में भी उन्हें समान अधिकार नहीं मिल पाते।

43 लोगों ने प्रतिकूल मौसम के कारण छोड़ी खेती:जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए अध्ययन में पाया गया कि 44 लोगों ने भूस्खलन का अनुभव किया, 43 लोगों को प्रतिकूल मौसम और फसल क्षति के कारण खेती छोड़नी पड़ी, 30 लोगों ने पशुपालन छोड़ दिया तथा 26 परिवारों ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी भूमि अथवा आवास खो दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर भूमि अधिकार रखने वाली महिलाओं पर जलवायु आपदाओं का प्रभाव अधिक गंभीर पड़ता है और पुनर्वास योजनाओं में उनकी भागीदारी भी सीमित रह जाती है।

अध्ययन में प्रस्तुत केस स्टडीज से यह भी स्पष्ट हुआ कि महिलाओं के भूमि अधिकार केवल कानूनी प्रावधानों का विषय नहीं हैं, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, पारिवारिक निर्णयों और संरचनात्मक सहयोग पर भी निर्भर करते हैं। कई महिलाओं ने बताया कि संपत्ति में उनका अधिकार होने के बावजूद सामाजिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएं उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने से रोकती हैं। वहीं कुछ मामलों में परिवार के सहयोग और जागरूकता ने महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने में मदद की। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि महिलाओं की कानूनी जागरूकता बढ़ाने, भूमि संबंधी दस्तावेजों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने, पंचायत स्तर पर सहायता तंत्र विकसित करने तथा जलवायु आपदाओं के बाद पुनर्वास नीतियों में महिलाओं के भूमि अधिकारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी व्यापक बदलाव आवश्यक हैं। वरिष्ठ पत्रकार अर्चना फुल ने कहा कि भूमि एवं संपति में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जन आंदोलन की जरूरत है। हर व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक होना होगा तभी समाज में बदलाव आएगा। पितृसत्ता की प्रथा आज के वक्त में बदल रही है। आज जब महिलाएं अपने मायके में भूमि पर हक जताने लगती है तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कई रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते है। कई बहने भाइयों से भूमि लेना ही नहीं चाहती है ताकि उनके रिश्ते के कोई दरार न आए। कई जगह पर ससुराल में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। अगर उन्हें पैतृक संपति में हक मिले तो अपने बच्चों का पालन पोषण और अपने जीवन को सही दिशा देने में अहम भूमिका हो सकती है। मां-बाप को भी सोचना होगा कि बेटों की तरह बेटियों का भी संपति में हक है और वो हक हर हाल में देना है।

इस दौरान पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट पालमपुर की संस्थापक रजनी व्यास, एकल नारी संगठन की संस्थापक निर्मल चंदेल, एवजिन फाउंडेशन की निदेशक डॉ निशा सिंह, संघपाल संस्थापक मुक्ति प्रोजेक्ट, चेयरपर्सन पीएमवीटी बिमला विश्वप्रेमी, प्रोग्राम मैनेजर शालिनी सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे।

बल्लेबाजों में खौफ पैदा करना है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए गुरनूर बराड़ ने भरी हुंकार; बैटर्स को दी बड़ी चेतावनी

पंजाब के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और वनडे सीरीज के लिए चुना गया। उन्हें टेस्ट मैच में खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए इस खिलाड़ी ने डेब्यू किया। उन्होंने डेब्यू पर तीन विकेट चटकाए और फिर दूसरे मुकाबले में भी उतने ही विकेट हासिल किए। शानदार प्रदर्शन के बाद बराड़ ने अपने आइडल और साउथ अफ्रीका के पूर्व महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन को लेकर बात की है।

बराड़ ने स्टेन की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि स्टेन सात से आठ सालों तक गेंदबाजी में नंबर वन रहे। जब वे भागते थे, तो ऐसा लगता था कि कुछ होने वाला है। बरार उनकी इस आक्रामकता से काफी प्रभावित हैं और उनकी तरह गेंदबाज बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने चयन को लेकर भी बात की। गुरनूर का मानना है कि भारतीय टीम में चयन होना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है।

डेल स्टेन को अपना आइडल मानते हैं बराड़

जियोस्टार पर बात करते हुए बराड़ ने कहा, मेरे पसंदीदा गेंदबाज डेल स्टेन हैं। 7-8 सालों तक वे नंबर वन बने रहे, जो बड़ी उपलब्धि है। इस तरह की निरंतरता बहुत ही कम देखने को मिलती है। उन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए बल्कि बल्लेबाजों के मन में अपना खौफ भी पैदा कर दिया था। जब वे गेंदबाजी के लिए दौड़ते थे, तो ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे उनका अंदाज बहुत पसंद है। वे सिर्फ विकेट नहीं लेना चाहते थे बल्कि दबदबा बनाना चाहते थे। मुझे उनका नजरिया बहुत पसंद है और मैं उनकी तरह ही गेंदबाज बनना चाहता हूं।

बराड़ ने भारतीय टीम में सेलेक्शन को लेकर की बात

बराड़ ने भारतीय टीम में अपने चयन को लेकर भी बात की। उनका कहना है कि जब टीम का एलान हुआ, तो वे सो रहे थे और एक दोस्त ने उन्हें इसकी खबर दी थी। युवा तेज गेंदबाज ने कहा, हर प्रैक्टिस सेशन से पहले मैं 45 मिनट की नींद लेता हूं, ये मेरा रूटीन है। जिस दिन टीम की घोषणा हुई, उस दिन भी मैं सो रहा था। मेरे दोस्त का फोन आया और उसने बताया कि मेरा सेलेक्शन हो गया है।

मुझे टेस्ट टीम में चुने जाने की उम्मीद थी लेकिन मेरा वनडे में सेलेक्शन हो गया। ये मेरे लिए एक जबरदस्त एहसास था और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरे माता-पिता ने फोन किया और वे भावुक हो गए।

मैं खुद को साबित करना चाहता हूं : बराड़

युवा पेसर ने आगे कहा, सभी क्रिकेटर का सपना होता है कि वो इंडिया के लिए खेले। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मेरा टीम में सेलेक्शन हुआ है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो मेरा लक्ष्य यहां तक पहुंचना था। अब जब मैं यहां हूं, तो मेरी सोच नहीं बदलने वाली है। मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं और सफल होना चाहता हूं। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक हूं, फिर चाहे वो मेरा पहला मैच हो या फिर 100 वां मैच।

ईशान किशन और ऋषभ पंत में से वर्ल्ड कप 2027 के लिए किसे मिलेगा साउथ अफ्रीका का टिकट? पूर्व भारतीय दिग्गज ने बताया नाम

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि ईशान किशन वर्ल्ड कप 2027 के चयन के लिए ऋषभ पंत से आगे हो गए हैं। अश्विन का कहना है कि किशन विश्व कप में चयन की रेस में पंत से आगे हैं। हालांकि, उनका मानना है कि ऋषभ टीम में चयन के दावेदार हैं। अगर उन्हें बाहर किया जाता है, तो उनके साथ अन्याय होगा।

गौरतलब है कि किशन ने पिछले कुछ समय से सफेद गेंद की क्रिकेट में पंत को काफी पीछे छोड़ दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी पंत का नाम नहीं था लेकिन ईशान प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। आईपीएल 2026 में भी पंत बल्ले से अच्छा नहीं कर सके लेकिन ईशान ने शानदार खेल दिखाया। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी किशन खेल रहे हैं और दूसरे मुकाबले में शतक लगाया। इसके बाद अश्विन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है।

रविचंद्रन अश्विन वे ईशान किशन को बताया बैकअप विकेटकीपर

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, मुझे लगता है कि केएल राहुल विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद होंगे। ईशान किशन को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जगह मिल सकती है। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये ऋषभ पंत के साथ गलत होगा। पंत ने वनडे क्रिकेट में मध्य क्रम में खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। किशन ने शानदार पारी खेली है लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अश्विन ने ईशान के शतक की तारीफ की लेकिन अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण पर सवाल उठाया। उन्होंने अफगानी गेंदबाजी के गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। अश्विन ने कहा, अफगानिस्तान के पास जो गेंदबाजी आक्रामण है, वो अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान को बुरी तरह से हराने के आधार पर किशन को विश्व कप के लिए नहीं चुनना चाहिए।

'टीम के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं थी', डीआर कांगो के खिलाफ ड्रॉ के बाद रोनाल्डो ने किया पुर्तगाल का बचाव

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल फुटबॉल टीम की शुरुआत निराशाजनक हुई है। टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में पुर्तगाल को डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टीम का बचाव किया है।

रोनाल्डो ने कहा कि डीआर कांगो के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पुर्तगाल टीम के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं थी। रोनाल्डो खुद इस मुकाबले में कोई गोल नहीं कर सके। रोनाल्डो के तीनों शॉट गोल पोस्ट से बाहर चले गए। रोनाल्डो ने मैच के बाद पुर्तगाल के 'स्पोर्ट टीवी' से एक छोटी बातचीत में कहा, कुछ भी कमी नहीं थी, फुटबॉल ऐसा ही है। हम जीत भी सकते थे।

अपने करियर के छठे वर्ल्ड कप के पहले मैच में रोनाल्डो का एक भी शॉट गोल पोस्ट में नहीं पहुंचा। यह दूसरी बार भी है जब उन्होंने वर्ल्ड कप मैच में 90 मिनट तक टारगेट पर कोई शॉट नहीं मारा।

रोनाल्डो के करियर का यह 23वां वर्ल्ड कप मैच था। वह फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर आ गए हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की तरफ से 10 बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट (वर्ल्ड कप और यूरो कप) खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 33 शॉट खेले हैं, जिसमें से 11 शॉट टारगेट पर पहुंचे हैं।

पुर्तगाल ने डीआर कांगो के खिलाफ 75 प्रतिशत से ज्यादा समय तक गेंद पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन टीम मुकाबले में दूसरा गोल करने में नाकाम रही।

पुर्तगाल ने मैच में अपना पहला गोल छठे मिनट में किया। जोआओ नेवेस ने टीम के लिए पहला गोल दागा। हालांकि, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में योआन वीसा ने डीआर कांगो की ओर से पहला गोल करते हुए स्कोर को पहले हाफ के अंत में बराबर कर दिया। इसके बाद डीआर कांगो के डिफेंस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पुर्तगाल को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया।

पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने रोनाल्डो के खराब प्रदर्शन का बचाव किया। उन्होंने कहा, जब आपको गोल की जरूरत हो, तो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को बेंच पर बैठाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि रोनाल्डो डिफेंडर्स को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बाकी खिलाड़ियों को गोल करने के लिए जरूरी जगह मिल पाती है। पुर्तगाल अब अगले मुकाबले में मंगलवार को उज्बेकिस्तान से भिड़ेगा।

युवाओं को नशे से दूर रखने में समाज का सहयोग अपेक्षित - मनमोहन शर्मा

» प्रथम न्यूज । सोलन
18 जून (बी.शर्मा)

उपायुक्त सोलन मनमोऊहन शर्मा ने कहा कि नशे के विरुद्ध प्रभावी जन जागरूकता ही इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने का सशक्त माध्यम है।

मनमोहन शर्मा आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर में एंटी चिट्टा जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। मनमोहन शर्मा ने कहा कि चिट्टा एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन समाज विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेलकूद तथा रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज नशा प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच गया है। युवाओं को चिट्टा व अन्य मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए प्रशासन व नागरिकों को मिलकर कार्य

करना होगा ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने सभी से आग्रह किया नशे से जुड़ी किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को प्रशासन व पुलिस तक पहुंचाएं ताकि इसे रोका जा सके। उन्होंने कहा कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि ज़िला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से एंटी चिट्टा अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है ताकि नशे पर रोक लगाई जा सके।

मनमोहन शर्मा ने अध्यापकों व अभिभावकों से भी आग्रह किया कि बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों की आदतों, मेलजोल व अन्य कार्यों पर नज़र रखें और किसी भी प्रकार के परिवर्तन को समझें ताकि उन्हें नशे की ओर जाने से रोका जा सके। इस अवसर पर छात्रों द्वारा नशा निवारण विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत धर्मपुर के प्रधान महेश गुप्ता, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर की प्रधानाचार्य धर्मवीर कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पाठशाला के अध्यापक व छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे।

ग्राम पंचायतें गांव में सरकार की सबसे नजदीकी इकाई: राजेश धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने नवगठित कुठेड़ा-मरहाणा ग्राम पंचायत का किया शुभारंभ

» प्रथम न्यूज । बिलासपुर
18 जून (जितेंद्र गौतम)

नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवगठित कुठेड़ा-मरहाणा ग्राम पंचायत के कार्यालय का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर नवगठित ग्राम पंचायत को शुभकामनाएं देते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने ऐसी चार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया है, जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से अत्यंत बड़ी थीं। इनमें कुठेड़ा-मरहाणा, हरितल्यांगर, देहरा-हटवाड़ तथा छंदोह ग्राम पंचायतों का गठन शामिल है। उन्होंने कहा कि इन ग्राम पंचायतों के गठन की मांग काफी समय से लंबित थी, जिसे वर्तमान सरकार ने पूरा किया है, ताकि इन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को गति मिल सके तथा लोगों को घर-द्वार के समीप ही पंचायत संबंधी सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायतों का गठन गैर-राजनीतिक आधार पर किया जाता है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को आमजन एवं जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने तथा सरकारी योजनाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसे अनेक पात्र लोग हैं, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधि पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने तथा जरूरतमंदों की आवाज बनकर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर पेयजल, विद्युत आपूर्ति, बेहतर शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा नशा उन्मूलन की दिशा में प्रभावी प्रयास करने का भी आह्वान किया।

राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकार ने ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की हैं। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण स्तर पर ही लोगों के छोटे-मोटे मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे न केवल लोगों को घर-द्वार पर न्याय मिलेगा, बल्कि उन्हें न्यायालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी तथा समय एवं धन दोनों की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिम परिवार योजना के तहत प्रदेश के 1.20 लाख ऐसे पात्र परिवारों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है, जिन्हें सरकारी सहायता की सर्वाधिक आवश्यकता है। इन परिवारों को 1,500 रुपये की मासिक आर्थिक मदद के साथ-साथ 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सबसे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवहन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए हैं। इनके परिणामस्वरूप प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान से उभरकर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 150 से अधिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। इनमें घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के घुमारवीं, हटवाड़, भराड़ी तथा कपाहड़ा विद्यालय भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में औहर तथा डंगार विद्यालयों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसी प्रकार अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी चिकित्सकों एवं अन्य आवश्यक पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा गया है। भराड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑटो एनालाइजर तथा रंगीन एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बम्म में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का कार्य प्रगति पर है, जबकि करयालग में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त घुमारवीं के लिए 33 केवी विद्युत उपकेंद्र स्वीकृत हो चुका है, जिससे क्षेत्र की विद्युत संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।

उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करता है, तो वे इस संबंध में 1100 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि आमजन को पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान की मांग पर गांव के विभिन्न संपर्क मार्गों के लिए 10-10 लाख रुपये तथा दो शेडों के निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त नवगठित पंचायत के लिए 10 कुर्सियां तथा दो पंखे भी स्वीकृत किए।

इससे पूर्व उन्होंने स्थानीय शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

इससे पहले नवगठित ग्राम पंचायत कुठेड़ा-मरहाणा की प्रधान नीलम शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा पंचायत गठन के लिए समस्त पंचायतवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने पंचायत की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित मांगपत्र भी प्रस्तुत किया।

इस दौरान विभिन्न महिला मंडलों तथा स्थानीय स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर एसडीएम गौरव चैधरी, खंड विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, नायब तहसीलदार भराड़ी प्यारे लाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन चंबेल सिंह, पंचायत प्रधान नीलम शर्मा, ब्लॉक समिति सदस्य नीलम ठाकुर एवं उषा ठाकुर, पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

झंडूता में सड़कों का होगा कायाकल्प, विधायक जीतराम कटवाल के प्रयासों से 90 लाख मंजूर

» प्रथम न्यूज । बिलासपुर
18 जून (जितेंद्र गौतम)

झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न सड़कों का कायाकल्प जल्द होगा। विधायक जीतराम कटवाल के प्रयासों से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आधा दर्जन से अधिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण और रखरखाव के लिए लगभग 90 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इनमें से बरठीं चैक से कृषि विज्ञान केंद्र तक वाया सिविल अस्पताल सड़क के लिए 32 लाख, बागड़ा-गुग्गा-गेहड़वीं, बैहरन-कोहली-गालियां, बलघाड़-जब्बल-पपलाह-मटेरी और दोकडू-नेरी सडक के लिए 12-12 लाख तथा तांबड़ी-श्री नयनादेवी माता मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर लेहड़ से शाहतलाई मेन रोड तक सड़क के लिए 5-5 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टेट फंड से दसलेहड़ा-खमेहड़ाकलां पुल व अप्रोच रोड के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये भी मुहैया करवाए हैं।

जीतराम कटवाल ने कहा कि वह झंडूता क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। उनका लक्ष्य है कि कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से अछूता न रहे। साथ ही हर परिवार तक सुविधाएं पहुंच सकें। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को हर गांव और घर तक पहुंचाना शुरू से ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस संकल्प के साथ वह क्षेत्र के विकास के लिए दिन-रात काम करने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह संबंधित क्षेत्रों के विकास, लोगों की सुविधा और गांवों की समृद्धि की दिशा में निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम है। आवागमन का माध्यम होने के साथ ही अच्छी सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों के द्वार भी खोलती हैं। इससे झंडूता विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकेंगे।

जीतराम कटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर एक नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा देश के सामने रखे गए विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर मूर्त रूप प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। सड़क, डिजिटल सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचा गांवों तक पहुंचाकर आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में झंडूता क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। दूरदराज के गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने, संपर्क सड़कों की हालत सुधारने और लोगों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम लगातार जारी है।

प्रथम न्यूज
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक
राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय
Website : www.prathamnews.in

संक्षिप्त न्यूज

IDFC बैंक फ्रॉड केस में IAS अधिकारी गिरफ्तार

पंचकूला (पुनीत महाजन)- CBI ने पंचकूला नगर निगम में हुए करोड़ों रुपये के फंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन निगम कमिश्नर और वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी श्रीराम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मिलीभगत से अंजाम दिए गए इस खेल में सरकारी पैसे को ठिकाने लगाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई ने एक्शन लेते हुए आईएएस अधिकारी के चंडीगढ़ और करनाल स्थित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि यह पूरा खेल नियमों को ताक पर रखकर रचा गया। पंचकूला नगर निगम का खाता चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खोला गया था। ये हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के नियमों के पूरी तरह खिलाफ था।

खाता खोलते वक्त ही फॉर्म में ऐसी जानकारियां भरी गईं, जिससे आगे चलकर होने वाले फर्जीवाड़े को आसानी से छुपाया जा सके। इसके बाद तत्कालीन कमिश्नर आर.के. सिंह ने बैंक अधिकारियों और बिचौलियों के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश रची।

पीएम-किसान की 23वीं किस्त 20 जून को होगी जारी

9.44 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 18,880 करोड़

नई दिल्ली (एएम नाथ)- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। लाभार्थियों में 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित कई केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

कृषि मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी की गई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के 45.35 लाख से अधिक किसानों को 907.21 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिलेगी। इसके साथ ही वर्ष 2019 से अब तक राज्य में पीएम-किसान के तहत कुल वितरण 15,055 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एपीस्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल हैं। फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2026-27 में पश्चिम बंगाल के लगभग 1.10 करोड़ किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती को बताया स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का अभियान

कानपुर (सुनील बाजपेई)- गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्राकृतिक खेती केवल कृषि पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का अभियान है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और पेस्टीसाइड के बढ़ते प्रयोग ने धरती की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाया है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाला है। इसअवसर पर किसानों को सम्मानित करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि, 12 सालों में हमने बदलते भारत को देखा जो बिना रुके थके, चल रहा है। अपने विरासत व विकास को आगे बढ़ा रहा है भारत।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंनेकहा कि प्राकृतिक खेती केवल कृषि पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का अभियान है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और पेस्टीसाइड के बढ़ते प्रयोग ने धरती की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाया है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाला है। सीएसए परिसर में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय लोग हैंडपंप और तालाब का पानी पी लेते थे, लेकिन आज किडनी, लीवर और अन्य गंभीर बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे खानपान और रसायनयुक्त कृषि का प्रभाव भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था अन्न के नाम पर जहर परोसने का काम नहीं कर सकती, इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर लौटना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने गोसंरक्षण को प्राकृतिक खेती से जोड़ते हुए कहा कि हम सभी गोमाता की पूजा करते हैं। गोआधारित खेती से गोवंश की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि शार्टकट के रास्ते अपनाने के कारण आज कई समस्याएं सामने आई हैं। यदि किसान गाय को परिवार का हिस्सा बनाएंगे तो खेती भी मजबूत होगी और गोवंश भी सुरक्षित रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी रहे । इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे।

सराज की तीनों पंचायत समितियों पर भाजपा का ऐतिहासिक कब्जा : जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा, आगे ट्रिपल इंजन की गति से होगा विकास, पंचायतीराज चुनावों से मिला बड़ा संदेश

» प्रथम न्यूज । मंडी
18 जून (एएम नाथ)

मंडी जिला के जंजैहली में आयोजित पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक सभा को संबोधित करते हुए इसे सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों में सर्वसम्मति से भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतनी शानदार और प्रचंड जीत के रूप में दर्ज हुआ है। तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई कि उन्हें ढूँढे भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिले। जयराम ठाकुर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि वे खुद प्रदेश के पंचायती राज मंत्री रहे और पांच वर्षों तक मुख्यमंत्री के गरिमामयी पद पर भी आसीन रहे, लेकिन उनके उस कार्यकाल के दौरान भी जमीनी स्तर पर पार्टी के इतने अधिक प्रत्याशी जीतकर कभी नहीं आए थे, जो इस बार की इस शानदार सफलता को बेहद खास और ऐतिहासिक बनाता है। उन्होंने भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जंजैहली ब्लॉक पूरी तरह से हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जबकि बालीचौकी ब्लॉक हमारे पड़ोस के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के साथ और गोहर ब्लॉक हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र के साथ सांझा रूप से अपनी सीमाएं साझा करता है। उन्होंने इन तीनों महत्वपूर्ण ब्लॉकों में पार्टी के नेतृत्व के फैसलों का सम्मान करते हुए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने के लिए सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया और साथ ही पार्टी के समर्पित, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से एक विशेष आग्रह किया कि वे इन सभी जन प्रतिनिधियों का धरातल पर पूरा सहयोग और मार्गदर्शन करें ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले समय में जीते हुए ऊर्जावान सदस्यों को भाजपा संगठन में बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ और अधिक मजबूत होगी। अतीत के चुनावों की कड़वी यादों और राजनीतिक उठापटक का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने चुटकी ली और कहा कि पूर्व में हुए इन स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करने के बाद अक्सर सदस्यों को विरोधी दलों की खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए छुपाने, बाड़ेबंदी करने और अज्ञात अज्ञात जगहों पर ठहराकर रखने की नौबत तक आ जाती थी, लेकिन अबकी बार कार्यकर्ताओं की अटूट निष्ठा और जनता के अपार विश्वास के कारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और यह सब क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के निस्वार्थ सहयोग के बिना कतई संभव नहीं था।

उन्होंने पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह प्रचंड और एकतरफा बहुमत देने के लिए सभी क्षेत्रवासियों का कोटि-कोटि धन्यवाद किया और कहा कि यह ऐतिहासिक जीत असल में उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं के दिन-रात के कड़े परिश्रम, पसीने और अटूट मेहनत की जीत है। जयराम ठाकुर ने गहरा विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि पंचायत समिति के सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा जनहित के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हुए संपूर्ण क्षेत्र के चहुंमुखी विकास में अपनी अग्रणी और सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इन पंचायतीराज चुनावों से प्रदेश की राजनीति में एक बेहद स्पष्ट और बड़ा संदेश गया है कि हिमाचल की जनता जमीनी स्तर से पूरी तरह भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है और वह वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों तथा विफलताओं से पूरी तरह तंग आ चुकी है। मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे से लौटते ही सार्वजनिक रूप से पूछ रहे थे कि भाजपा आखिर किस नैतिक आधार पर पंचायत चुनावों में अपनी जीत के बड़े-बड़े दावे कर रही है, तो आज मैं इस मंच से उन्हें पूरे आंकड़े सहित यह बताना चाहता हूँ कि हमने प्रदेश भर में 70 प्रतिशत से अधिक पंचायत प्रतिनिधि जीते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ हमारे साथ मजबूती से चल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी अब आपकी बारी है कि आप प्रदेश की जनता को बताएं कि आपके साथ कितने लोग चले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के झूठे दावे और भ्रामक आंकड़े जनता के सामने पेश करने से पूरी तरह बचना चाहिए था, क्योंकि यह जनमत सीधा-सीधा उनकी वर्तमान सरकार के खिलाफ आया है और आज समाज का हर वर्ग, चाहे वह कर्मचारी हो, युवा हो या किसान, इस सरकार के कुप्रबंधन से बेहद दु:खी है।

अंत में, उन्होंने सभी विजयी जन प्रतिनिधियों को पूरी तरह आश्वस्त करते हुए विश्वास दिलाया कि आगे आने वाला वक्त पूरी तरह से भाजपा का है और आने वाले समय में भाजपा ही पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाएगी, और जब देश के साथ-साथ पंचायत, प्रदेश और केंद्र तीनों स्तरों पर भाजपा की सरकार होगी, तो पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास ट्रिपल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ेगा।

पंजाब में चुनावी बिगुल : हरिमंदिर साहिब से दौरा शुरू करेंगे नितिन नवीन

पंजाब में संगठन मजबूत करने की कवायद, तीन दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली
18 जून (एएम नाथ)

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 20 जून से पंजाब के तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेककर करेंगे। इसके बाद वह दुर्गियाना मंदिर में भी दर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह उनका पंजाब का पहला दौरा होगा। अमृतसर से नवीन जालंधर और लुधियाना जाएंगे, जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। 21 जून को लुधियाना में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें करीब 7,500 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती का संदेश देंगे।

भाजपा नेताओं के अनुसार यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल के बिना अकेले लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व राज्य में संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। अमृतसर से दौरे की शुरुआत को सिख समुदाय तक पहुंच बनाने और पार्टी के प्रभाव को पारंपरिक शहरी हिंदू वोट बैंक से आगे बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

लुधियाना में प्रस्तावित सम्मेलन को मालवा क्षेत्र में भाजपा की संगठनात्मक ताकत प्रदर्शित करने की कोशिश माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस संदेश की अगली कड़ी है, जिसमें उन्होंने पंजाब में भाजपा के दम पर चुनाव लड़ने और राज्य के सर्वांगीण विकास का दावा किया था। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय संगठन सचिव बी.एल. संतोष ने भी पंजाब चुनावों की तैयारियों और दौरे की सफलता को लेकर आरएसएस के साथ समन्वय बैठक की है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा एलान

ग्रुप-C की सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20% आरक्षण, एलजी ने दी हरी झंडी

» प्रथम न्यूज । नई दिल्ली
18 जून (ब्यूरो)

दिल्ली सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार के विजन के तहत दिल्ली में पूर्व-अग्निवीरों को ग्रुप-ष्ट की सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) तरनजीत सिंह संधू ने आज बृहस्पतिवार (18 जून) को योजना को जल्द जमीन पर उतारने को लेकर मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।

इसके तहत दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, जेल और वन एवं वन्यजीव विभागों में ग्रुप C के सीधी भर्ती वाले पदों पर पूर्व-अग्निवीरों को 20 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसमें दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल, फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डन और वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड व वाइल्डलाइफ गार्ड के पद शामिल होंगे। सरकार के इस कदम से पूर्व-अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाना आसान हो जाएगा।

भर्ती नियमों में बदलाव और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एलजी ने सभी विभागों को 30 जून 2026 की डेडलाइन दी है। एलजी का मानना है कि पूर्व-अग्निवीरों का अनुशासन और ट्रेनिंग राजधानी के सिस्टम को और मजबूत बनाएगा।

उल्लेखनीय 8 जून 2026 को हुई बैठक में उन्होंने पहले दिल्ली फायर सर्विस में इनकी भर्ती का प्रस्ताव रखा था, जिसे अब दूसरे अहम विभागों में भी लागू किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि इन युवाओं को सरकारी ढांचे में लाने से विकसित दिल्ली का विजन आगे बढ़ेगा।

जिला स्तरीय समिति की बैठक में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण एवं विकास योजनाओं की समीक्षा

» प्रथम न्यूज । शिमला
18 जून (बी.शर्मा)

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज यहां बचत भवन में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा ने की। बैठक में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि जिला शिमला में कुल 2154 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 231 केंद्र अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें 207 केंद्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 25 प्रतिशत से कम तथा 24 केंद्रों में 25 प्रतिशत से अधिक है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला में 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 7 आंगनबाड़ी सहायिकाएं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं।

बैठक में जानकारी दी गई कि अल्पसंख्यक समुदाय के 475 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं, जिनमें से 379 बच्चों को विशेष पोषण कार्यक्रम के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है तथा 96 बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दी जा रही है। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 445 बच्चों का वजन एवं लंबाई मापी गई, जिनमें 432 बच्चे सामान्य पाए गए जबकि 13 बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित पाए गए। इसके अतिरिक्त 95 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी विभागीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के दौरान बताया गया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को आवासीय सुविधा सहित शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में शिक्षा खंड छौहारा के अंतर्गत आंधा स्थित विद्यालय में 100 छात्राएं अध्ययनरत हैं और वह शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी कर रही हैं।

उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली में 10 विद्यार्थियों को उर्दू विषय की शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन, पाठ्य-पुस्तकें तथा वर्दी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

बैठक में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की भी समीक्षा की गई। जिला में संचालित इस्लामिया मदरसा कासिमुल उलूम कुफार तथा मदरसा इस्लाहुल फिक्र मस्जिद बालूगंज में विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ नियमित विद्यालयी शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

जिला में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अल्पसंख्यक समुदाय के 391 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से 73 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि मनरेगा के तहत वर्ष 2025-26 में जिला शिमला में 280 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से 6 परिवारों को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर, राजकीय फार्मेसी कॉलेज रोहड़ू तथा राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) शिमला में भी अल्पसंख्यक समुदाय के 8 प्रशिक्षु विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित ऋण योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि टर्म लोन योजना के तहत 3750 लाभार्थियों को 115.63 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में 153 लाभार्थियों को 9.38 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत भी पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में जिला के 10 लाभार्थियों को 5.93 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नगर निगम शिमला द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की मलिन बस्तियों में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि बंगाला कॉलोनी टूटू, ईदगाह कॉलोनी, कुष्ठ रोगी कॉलोनी डाउनडेल फेज-1 तथा बंगाला कॉलोनी संजौली में विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2026 तक लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इन क्षेत्रों में नियमित सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान तथा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में एएसपी मेहर पंवर, जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस ममता पॉल सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।